रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 8, 1975/माघ 19, 1896
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 8, 1975/MAGHA 19, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश, और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notification issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1975

का० आ० 321.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन के लिए 132—सराडा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमृत लाल, निवासी गतोड़ा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यत उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अत', अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमृत लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०-वि० स०/132/72/(47)]
वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th January, 1975

S.O. 321.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amrit Lal, R/o Village Ghatod, Tehsil Sarada, District Udaipur, Rajasthan, a contesting candidate for General Elections to the Rajasthan Legislative Assembly held in March 1972 from 132-Sarada constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act 1951 and the Rules made thereunder;

2 And whereas the said candidate even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and whereas, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amrit Lal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/132/72/(47)
V. NAGASUBRAMANIAN, S

वित्त मंत्रालय

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

नई दिल्ली, 25 जनवरी 1975

का० आ० 322—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी, 1975 की 17 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

निर्गम विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	47,44,77,000		सोने का सिक्का और बुलियन —		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,52,68,000	
संचालन में नोट	6136,94,68,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
जारी किये गये कुल नोट		6184,39,45,000	विदेशी प्रतिभूतियां	141,73,97,000	
			जोड़		324,26,65,000
			रुपये का सिक्का		14,79,37,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5845,33,43,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		—
कुल देयताएं		6184,39,45,000	कुल आस्तियां		6184,39,45,000

तारीख 22 जनवरी 1975

एस० जगन्नाथन गवर्नर

17 जनवरी 1975 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	47,44,77,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,63 000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	3,96,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	284 00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	168,12,91,000
(स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	403,87,35,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	405,19,97,000
जमाराशियां		निवेश**	527,75,23,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :	..
(i) केन्द्रीय सरकार	58,40,04,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	
(ii) राज्य सरकारें	6,30,92,000	(ii) राज्य सरकारों को‡	169,53,23,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम —	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	522,89,27,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को*	79,75,50,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	16,07,11,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को**	372,38,88,000
		(iii) दूसरों को	11,59,65,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,58,25,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
(iv) अन्य बैंक	64,65,000	(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	67,71,90,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	16,48,59,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	—
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	63,50,00,000
(ग) अन्य	570,15,33,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	11,12,58,000
देय बिल	147,07,05,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	45,67,93,000
अन्य देयताएं	725,88,39,000	ऋण अग्रिम और निवेश :—	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	251,55,03,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	—
		अन्य आस्तियां	206,19,90,000
रुपये	2848,01,01,000	रुपये	2848,01,01,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं : परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल नहीं है ।

*रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 14,81,00,000/- रुपये शामिल है ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है ।

एस० जगन्नाथन गवर्नर

तारीख : 22 जनवरी, 1975

[सं० फ० 10/1/75-बी० ओ० 1]

च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

Ministry of Finance

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi the, 25 January, 1975

S.O. 322—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 17th day of January 1975

Issue Department

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	47,44,77,000		Gold Coin and Bullion:—		
			(a) Held in India	182,52,68,000	
Notes in circulation	6136,94,68,000				
			(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		6184,39,45,000	Foreign Securities	141,73,97,000	
			Total		324,26,65,000
			Rupee Coin		14,79,37,000
			Government of India Rupee Securities		5845,33,43,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total liabilities		6184,39,45,000	Total Assets		6184,39,45,000

Dated 22nd day of January 1975

S. JAGANNATHAN, Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 17th January 1975

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	47,44,77,000
		Rupee Coin	3,63,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,96,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	(a) Internal	168,12,91,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	403,87,35,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Balances Held Abroad*	405,19,97,000
		Investments**	527,75,23,000
		Loans and Advances to:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	169,53,23,000
Deposits:—		Loans and Advances to:—	
		(i) Scheduled Commercial Banks‡	79,75,50,000
(a) Government		(ii) State Co-operative Banks‡‡	372,38,88,000
(i) Central Government	58,40,04,000	(iii) Others	11,59,65,000
(ii) State Governments	6,30,92,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations Fund	
(b) Banks		(a) Loans and Advances to:—	
		(i) State Governments)	67,71,90,000
(i) Scheduled Commercial Banks	522,89,27,000	(ii) State Co-operative Banks	16,48,59,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	16,07,11,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	63,50,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,12,58,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,58,25,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
(iv) Others Banks	64,65,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	45,67,93,000
(c) Others	570,15,33,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	251,55,03,000
Bills Payable	147,07,05,000	(b) Investment in bond/debentures issued by the Development Bank	..
Other Liabilities	725,88,39,000	Other Assets	206,19,90,000
RUPEES	2848,01,01,000	RUPEES	2848,01,01,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

‡ Includes Rs. 14,81,00,000 advances to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡‡ Excluding Loans and Advanced from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 22nd day of January 1975.

S. JAGANNATHAN, Governor
C. MIRCHANDANI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1974

(आय-कर)

का० आ० 323.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-2) तारीख 18 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्धन करता है ।

उक्त अनुसूची में अंतिम क्रम सं० के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

1	2	3	4	5
आय-कर अधिकारी जे-वार्ड, कम्पनीज जिला 1, कलकत्ता ।	(क) पश्चिमी बंगाल राजक्षेत्र में निवास या कारबार करने वाले समस्त व्यक्ति जिनका अबतक निर्धारण नहीं किया गया है तथा जिनके विरुद्ध यह सूचना है कि वें तस्करी के क्रिया-कलापों में लगे हुए है या लगे हुए थे ।	सहायक आयुक्त निरीक्षण रेंज 25, कलकत्ता।	सहायक आय-कर आयुक्त अपील, रेंज-ई, कलकत्ता।	आयकर आयुक्त पश्चिमी बंगाल-I, कलकत्ता।
	(ख) समस्त व्यक्ति जिनके मामले आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 127 के अधीन समनुदेशित किए जा चुके है या इसके पश्चात् समनुदेशित किए जा सकेंगे ।			

यह अधिसूचना 6 दिसम्बर, 1974 से प्रभावी होगी ।

[सं० 779 (फा० सं० 187/11/74-2 (ए आई)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 22nd November, 1974

(Income Tax)

S.O. 323.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following additions to the Schedule annexed to its Notification No. I (F.No.55/233 63-II) dated the 18th May, 1964 as amended from time to time.

After the last Serial No. in the said Schedule the following shall be added:

1	2	3	4	5
Income-tax Officer, J-Ward, Companies District I, Calcutta.	(a) All persons resident or having business within the territory of West Bengal who have not been hitherto assessed and against whom there is information that they are or were engaged in smuggling activities.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range XXV, Calcutta.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Rang E, Calcutta.	Commissioner of income-tax, West Bengal-I, Calcutta.
	(b) All persons whose cases have been assigned or may hereafter be assignment u/s 127 of the I. T. Act, 1961.			

This Notification shall take effect from the 6th Dec., 1974

[No. 779(F. No. 187/11/74-II (AI)]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(आय कर)

नई दिल्ली, दिसम्बर, 1975

का० आ० सं० 324—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय-समय पर यथासंशोधित उसकी अधिसूचना सं० 774 (फा० सं० 187/10/74-आई० टी (ए० आई) तारीख 12 नवम्बर, 1974 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उससे उपाबद्ध अनुसूची में सं० 1 अतिरिक्त आय-कर आयुक्त कर्नाटक, बंगलौर के सामने स्तम्भ 3 के नीचे प्रविष्टि सं० 22 का लोप किया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित दो प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी ।

"22 आय-कर अधिकारी, न्यास सर्किल, बंगलौर ।

22क—आय-कर अधिकारी, विदेश अनुभाग बंगलौर ।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी"

[सं० 794 (फा सं० 187/10/74-आई० टी० (ए आई)]

वी० बी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

(Income-tax)

New Delhi, the 16th December, 1974

S.O. 324.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 774 (F. No. 187/10/74-II(AI) dated the 12th November, 1974 as amended from time to time.

Against No. 1 Additional Commissioner of Income-tax, Karnataka, Bangalore under Column 3 of the Schedule appended thereto, entry No. 22 shall be deleted and instead following two entries shall be added.

"22. Income-tax Officer, Trust Circle, Bangalore.

22A. Income-tax Officer, Foreign Section, Bangalore.

This notification shall come into force with immediate effect.

[No. 794 (F. No. 187/10/74-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1975

सीमा शुल्क

का० आ० सं० 325—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ को भाण्डागारण केन्द्र घोषित करता है ।

[सं० 3/75-सीमा शुल्क/फा० सं० 473/191/74-सीमा शुल्क-7]

डी० सरूप, अवर सचिव,

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 1st February, 1975

Customs

S.O. 325.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (5 of 1962) the Central Board of Excise and Customs hereby declares Lucknow in the State of Uttar Pradesh to be a warehousing station.

[No. 3/75-Customs/F. No. 473/191/74-Cus. VII]

D. SARUP, Under Secy.

(राजस्व बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1975

स्टाम्प

का० आ० सं० 326—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 1) की धारा 9 उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से जो इण्डस्ट्रीयल क्रेडिट एनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई द्वारा जारी किये जाने वाले नौ करोड़ रुपये मूल्य के डिबेन्चरों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है छूट देती है ।

[सं० 3/75 स्टाम्प/फा०स 73/471/74-सीयूएस 7]

जे० रामकृष्णन, अवर सचिव

(Department of Revenue and Insurance)

ORDER

New Delhi, the 29th January, 1975

Stamps

S.O. 326.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the debentures of the value of six crores of rupees, to be issued by the Industrial Credit Investment Corporation of India Limited, Bombay, are chargeable under the said Act.

[No. 3/75-Stamps/F No. 471/73/74-Cus. VII]

J. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी, 1975

का० आ० सं० 327—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के खंड (क) की धारा 2 के अनुसार केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत का हाई कमीशन, ढाका में सहायक श्री पी० के० शर्मा को तत्काल कौंसली एजेन्ट का कार्य करने को प्राधिकृत करती है ।

[फा० सं० टी० 4330/4/74]

राम लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 17th January, 1975

S.O. 327.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri P. K. Sharma, Assistant in the High Commission of India, Dacca to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T. 4330/4/74]

RAM LAL, Under Secy

वाणिज्य मन्त्रालय

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

बम्बई, 17 सितम्बर, 1974

का० आ० 328.—मर्वश्री ट्रेसा सेल्स कार्पोरेशन, बम्बई-1 को भाग 253-4 के अन्तर्गत आने वाले कीमती पत्थर अनकट एवं अनसेट के आयात के लिए 95449 रुपए का एक लाइसेंस स० 1382283 दिनांक 17-1-74 स्वीकृत किया गया था ।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) खो गया/अस्थानस्थ हो गया है ।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने रजिस्ट्रार एवं प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट, बम्बई के सम्मुख विधिवत् शपथ लेते हुए 3 50 रुपए के स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस स० 1382283 दिनांक 17-1-74 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को अनुलिपि लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए ।

लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की गई समझी जाती है ।

[फा० सं० एस-3/553/2155/43283/ए एम-74/एस सी-6]

यू० एस० रावत, उप-मुख्य नियंत्रक, कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

Bombay, the 17th September, 1974

S.O. 328.—M/s. Tressa Sales Corporation, Bombay-1 have been granted licence No. 1382283 dated 17-1-74 for Rs. 95449 for Import of Precious Stones Uncut and Unset falling under Part 253-IV.

They have now applied for duplicate copy of Exchange Control Copy of the said licence on the ground that the original licence (Exchange Control Copy) has been lost/misplaced.

In support of their claim, applicants have filed an affidavit on Rs. 3.50 Stamp Paper duly sworn before the Registrar and Presidency Magistrate Exsplande Court, Bombay.

I am satisfied that the original Exchange Control Copy of licence No. 1382283 dated 17-1-74 has been lost/misplaced and direct that the duplicate of the licence should be issued to the applicant.

The Original Exchange Control Copy of the licence Is treated as cancelled

[File No. S-3/553/2155/43283/AM-74/SC-6]

U. S. RAWAT, Dy. Chief Controller

for Jt. Chief Controller

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1975

(रबड़ नियंत्रण)

का० आ० 329—सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि रबड़ अधिनियम 1947 (1947 का 24) की धारा 6ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने श्री वी० भास्कर पिल्ले, भूतपूर्व लागत लेखा अधिकारी को 12 दिसम्बर, 1974 के पूर्वाह्न से सचिव, रबड़ बोर्ड कोट्टायम के पद पर नियुक्त किया है ।

[फाइल सं० 21(12)/74-प्लाट (बी)]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th January, 1975

(Rubber Control)

S.O. 329.—It is hereby published for the information of public that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6A of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government have appointed Shri V. Bhaskara Pillai, formerly Cost Accounts Officer in the Rubber Board, Kottayam, as Secretary, Rubber Board, Kottayam, with effect from the forenoon of the 12th December, 1974.

[F. No. 21(12)/74-Plant(B)]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1975

का०आ० 330.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्नन) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी० एम० एल०—359 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है, 1 जनवरी, 1975 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि इस वस्तु पर प्रतिबंध होने के कारण लाइसेंसधारी की लाइसेंस को चलाने में अब रुचि नहीं है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस सं० और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
1	सी एम/एल 359 20-11-61	मैसर्स बर्माशेल आयरन स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कं० आफ इंडिया लि० बर्मा-शेल हाऊस, बैलर्ड इस्टेट, बम्बई-1	डायएल्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव—	IS : 1054-1962 डाय-एल्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव

[सं० सी० एम० डी०/55 : 359]

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & CIVIL SUPPLIES

(Indian Standard Institution)

New Delhi, the 20th January, 1975

S.O. 330.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-359 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1-1-1975 on account of/due to as the party is not interested due to this beong a nanned item

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process governed by the Licensees cancelled	Relevant Indian Standard
1	2	3	4	5
1	CM/L 359 20-11-61	M/s. Burma-Shell Oil, Storage & Distributing Co of India Ltd., Burma-Shell House, Ballard Estate, Bombay-1	Dieldrin EC	IS: 1054-1962 Specification for Dieldrin EC

[CMD/55: 359]

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1975

का०आ० 331.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 3 के उप-विनियम (4) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अनुसार नीचे अनुसूची में जिस IS : 6747-1972 के ब्यौरे दिए गए है, उसके उपबंधों में मानक चिह्नन के उपयोग में गति लाने के उद्देश्य से परीक्षात्मक रूप में संशोधन किए गए है । इन संशोधनों के द्वारा भारतीय मानक के अनुरूप बने माल की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये संशोधन तुरन्त ही लागू हो जाएंगे ।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक जिसके उपबंधों में संशोधन किया गया है ।	भारतीय मानक के उपबंधों के किए गए संशोधन का विवरण
1.	IS : 6747-1972 ब्यूटिंग गम और बबूल गम की विशिष्ट	(पृष्ठ 5, सारणी 1, क्रम संख्या (iv) के सम्मुख स्तम्भ 3)— "4.5" के स्थान पर "2.5" कर लीजिए । (पृष्ठ 5 सारणी 1, क्रम संख्या (iv) के सम्मुख स्तम्भ 4)— "5.5" के स्थान पर 2.75" कर लीजिए ।

[सं० सी० एम० डी०/13:4]

(Department of Industrial Development)

New Delhi, 24th January, 1975

S.O. 331.—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of IS:6747-1972, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This notification shall come into force with immediate effect.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard, the provisions of which have been modified	Particulars	the Modifications made to the provisions
1.	IS:6747-1972 Specification for Chewing gum and bubble gum	[Page 5, Table 1, col. 3 against Sl. No. (iv)]	—Substitute '2.5' for 4.5]
		[Page 5, Table 1, col. 4 against Sl. No. (iv)]	—Substitute '2.75' for '5.5'

[No. CMD/13:4]

का० आ० 332.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1965 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-3483 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, फर्म द्वारा अपना नाम बदल देने के कारण 16 दिसम्बर, 1974 से रद्द कर दिया गया है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गये लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
1.	सी एम/एल-3483 13-7-73	मैसर्स स्टैण्डर्ड मिनिरल प्रोडक्टस लि०, सुभाष नगर जोगेश्वरी (पूर्व) बम्बई-60	डी० डी० टी० पायसनीय तेज द्रव	IS : 633-1956 डी०डी०टी० पायसनीय तेज द्रव की विशिष्टि

[सं० सी० एम०डी०/55:3483]

S. O. 332.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-3483 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 16-12-74 due to change in the name of the firm.

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process governed by the Licensees cancelled	Relevant Indian Standard
1	2	3	4	5
1	CM/L-3483 13-7-73	M/s. Standard Mineral Products Ltd., Subhash Nagar, Jogeshwar (East) Bombay-60	DDT EC	IS:633-1956 Specification for DDT EC

[No. CMD/55 : 8483]

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1975

का०आ० 333.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन् चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन प्रमाणन मुहर लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए है, प्रत्येक के सम्मुख स्तम्भ (6) में दी गई तिथियों से स्थगित कर दिए गए है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और जारी करने की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	वस्तु प्रक्रिया तथा तत्सम्बन्धी भारतीय मानक का शीर्षक	एस ओ संख्या और लाइसेंस के छपने की तिथि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सी एम/एल-376 16-1-1962	सुरमा वैली सा मिल्स प्रा० लि०, डाकघर भंगबाजार, जिला कछार, असम	चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड के तख्ते— IS : 10-1970	एस० ओ० 1062 दिनांक 7-4-1962	31-12-1973 के बाद स्थगित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	सी एम/एल-480 29-11-1962	जय इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, एम/52, इंडस्ट्रियल एरिया, जलधर शहर	धातु चढ़े स्विच, 15 अम्पी 250 वोल्ट, एचमी और एम ई एम टाइम फ्यूज तथा वाहकों वाले-- IS : 4064-1967	--	31-1-1974 के बाद स्थगित
3.	सी एम/एल-791 30-9-1964	एलूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, जयकाय नगर, आसनसोल के निकट (प० बंगाल) (कार्यालय : 7 कौसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता-1)	पूर्ण एलूमिनियम चालक और इस्पात प्रबलित एलुमिनियम चालक-- IS : 398-1961	एस ओ 3762 दिनांक 31-10-1964	15-10-1973 के बाद स्थगित
4.	सी एम/एल-1055 20-4-1965	इंडियन मिनिरल इंडस्ट्रीज लि०, ट्रेंचिंग ग्राउंड, एप्रोच रोड, अलीपुर, 24-परगना	बी एच सी धूलन पाउडर-- IS : 561-1962	एस ओ 1592 22-5-1965	15-3-1974 के बाद स्थगित
5.	सी एम/एल-1110 8-7-1965	दि एलूमिनियम इंडस्ट्रीज लि०, राम चन्द्र पुरम डाकघर, हैदराबाद-32	पोलीथीन रोधित और पी वी सी खोल वाले केबल-- IS : 1596-1962	एस ओ 2667 दिनांक 28-8-1965	15-11-1973 के बाद स्थगित
6.	सी एम/एल-1194 10-1-1966	दि बंगाल मशीनरी कं० प्रा० लि०, 9ए, न्यू टांग्रा रोड, कलकत्ता-46	डब्ल्यू सी तथा मूत्रालयों के लिए पलश की टंकिया-- IS : 774-1971	एस ओ 525 दिनांक 19-2-1966	15-9-1973 के बाद स्थगित
7.	सी एम/एल-1305 28-7-1966	असम हार्डबोर्ड लि०, पानीखेती (गौहाटी के समीप) असम (कार्यालय : 21 ए-विप्लवीरास विहारी रोड, कलकत्ता-1)	सामान्य फाइबर के हार्ड बोर्ड-- IS 1658-1966	एस ओ 2600 दिनांक 27-8-1966	31-1-1974 के बाद स्थगित
8.	सी एम/एल-1403 3-3-1967	इंडियन मिनिरल इंडस्ट्रीज लि०, ट्रेंचिंग ग्राउंड, एप्रोच रोड, अलीपुर, 24-परगना	बी एच सी जल विसर्जनीय तेज चूर्ण-- IS : 562-1962	एस ओ 1531 दिनांक 29-4-1967	15-3-1974 के बाद स्थगित
9.	सी एम/एल-1624 16-1-1968	एम एन चटर्जी एण्ड कं०, पी 48, बनारस रोड, हावड़ा-5	बी-बेरल के लिए बी-खांचेदार गिर्री-- IS : 3142-1965	एस ओ 684 दिनांक 25-2-1968	5-1-1974 के बाद स्थगित
10.	सी एम/एल-1813 14-10-1968	शालीमार बिस्कुट (प्रा०) लि०, उप्पल इंडस्ट्रियल इस्टेट, वारंगल रोड, उप्पल, हैदराबाद-13	बिस्कुट-- IS : 1011-1968	एस ओ 4257 30-11-1968	15-10-1973 के बाद स्थगित
11	सी एम/एल-1837 20-11-1968	दि एलुमिनियम इंडस्ट्रीज लि०, रामचन्द्र पुरम डाकघर, हैदराबाद-32	पी वी सी रोधित केबल-- IS : 694(भाग 2)-1964	एस ओ 4594 दिनांक 28-12-1968	15-11-1973 के बाद स्थगित
12.	सी एम/एल-1838 20-11-1968		ताप नम्य रोधित अग्निसह केबल-- IS : 3035 (भाग 2)-1965	एस ओ 4594 दिनांक 28-12-1968	15-11-1973 के बाद स्थगित
13.	सी एम/एल-1840 22-11-1968	इंडिक्ले, प्लाट सं० 2, उद्योग नगर, गोरे गांव, बम्बई-62	मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव-- IS : 2567-1963	एस ओ 4594 दिनांक 28-12-1968	30-11-1973 के बाद स्थगित
14.	सी एम/एल-1843 27-11-1968		ताम्र आक्सीक्लोराइड जल-विसर्जनीय तेज पाउडर-- IS : 1507-1966		30-11-1973 के बाद स्थगित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	सी एम/एल-2010 8-7-1969	श्री वैनेस एण्ड क०, 84, इंडस्ट्रियल सर्वब यशवंतपुर, बंगलौर-22	पशुओं के लिए मिश्रित आहार— IS : 2052-1968	एस ओ 3585 दिनांक 6-9-1969	31-7-1973 के बाद स्थगित
16.	सी एम/एल-2075 22-9-1969	इंडियन वायर स्टील प्राडक्ट्स, 10, स्टार्क रोड, लिलूवा, हावड़ा	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मृदु इस्पात के तार— IS : 280-1972	एस ओ 1235 दिनांक 4-4-1970	28-2-1974 के बाद स्थगित
17.	सी एम/एल-2090 30-9-1969	दि इंडस्ट्रियल गैसेस लि०, 146, अंतूल रोड, हावड़ा-3 (पं० बंगाल) (कार्यालय : 15 गणेशचन्द्र ऐवेन्यू, कलकत्ता-1)	आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर— IS : 1861-1966	एस ओ 4310 दिनांक 25-10-1969	30-9-1973 के बाद स्थगित
18	सी एम/एल-2123 27-10-1969	स्वास्तिक स्टील एण्ड एलाइड प्राडक्टस, 8/1, नूतन पाड़ा रोड, लिलूवा, हावड़ा	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977-1969	एस ओ 4849 दिनांक 6-12-1969	31-10-1973 के बाद स्थगित
19.	सी एम/एल-2182 24-12-1969	दि बंगाल इलैक्ट्रिक कर्सन, 33/1, बीनू लेन, कदम तल्ला, हावड़ा-1	डोर-क्लोजर (द्रव नियंत्रित) IS : 3564-1970	एस ओ 4371 दिनांक 7-2-1970	31-12-1973 के बाद स्थगित
20.	सी एम/एल-2356 1-7-1970	के आर स्टील यूनियन प्रा० लि०, 16—डी०, इंडस्ट्रियल एरिया, कल्याणी, जिला नदिया (पं० बंगाल), (कार्यालय :33 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी इस्पात के सरिया— IS : 1786-1966	एस ओ 2109 . दिनांक 29-5-1971	30-9-1973 के बाद स्थगित
21.	सी एम/एल-2403 9-9-1970	मैसूर सीमेंट लि०, आदित्य पाटन अम्मासंद्र, डाकघर टुम्कुर जिला (कार्यालय:विधान बीठि, काफी बोर्ड बिल्डिंग (चौथी मंजिल) बंगलौर-1)	साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट- IS : 269-1967	एस ओ 3349 दिनांक 11-9-1971	15-9-1973 के बाद स्थगित
22.	सी एम/एल-2420 6-10-1970	चालिहा रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, 13, चंद्रीतल्ला लेन, 55, नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड, तालीगंज, कलकत्ता-40	गाल्वीकृत रोकतार की लड़— IS : 2141-1968	एस ओ 561 दिनांक 30-1-1971	15-3-1974 के बाद स्थगित
23.	सी एम/एल-2436 27-10-1970	दि नेशनल इसुलेटेड केबल कं० आफ इंडिया लि०, शामनगर-24 परगना (पं०बंगाल) (कार्यालय: निको हाऊस, हैयर स्ट्रीट, कलकत्ता-1)	खनिकों की टोपियों की बत्तियों के लचकीले, केबल IS : 2593-1964	एस ओ० 561 दिनांक 30-1-1971	15-11-1973 के बाद स्थगित
24.	सी एम/एल-2487 23-12-1970	दि रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल कं लि०, रामपुर (उ०प्र०)	रम— IS : 3811-1966	एस ओ 2014 दिनांक 22-5-1971	31-12-1973 के बाद स्थगित
25.	सी एम/एल-2488 23-12-1970	,,	जिन— IS : 4100-1967	एस ओ 2014 दिनांक 22-5-1971	31-12-1973 के बाद स्थगित
26.	सी एम/एल-2489	,,	ह्विस्कियां— IS : 4449-1967	एस ओ 2014 दिनांक 25-5-71	31-12-1973 के बाद स्थगित
27.	सी एम/एल-2490 23-12-1970	,,	ब्राडियां— IS : 4450-1967	एस ओ 2014 दिनांक 22-5-1971	31-12-1973 के बाद स्थगित
28.	सी एम/एल-2502 4-1-1971	निर्मल ट्रेडिंग कं० 75, क्षेत्र मित्र लेन, सलिकया (हावड़ा)	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970	एस ओ 5028 दिनांक 6-11-1971	31-12-1973 के बाद स्थगित
29.	सी एम/एल-2546 18-2-1971	रतन रि-रोलर्स प्रा० लि०, 6/1, काली मजूमदार रोड, डाकघर घुसूरी, हावड़ा (कार्यालय : 23/ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1)	संरचना इस्पात (मानक किस्म— IS : 226-1969	एस ओ 5037 दिनांक 6-11-1971	31-8-1973 के बाद स्थगित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	सी एम/एल-2547 18-2-1971	रतन दि रौजर्स प्रा० लि०, 6/1, काली मजूमदार रोड, डाकघर घुसूरी, हावड़ा (कार्यालय : 23/ए नेताजी सुभाषरोड,कलकत्ता-1)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977-1969	एस ओ 5037 दिनांक 6-11-1971	31-8-1973 के बाद स्थगित
31.	सी एम/एल-2559 19-2-1971	भुवनेश्वरी पुल्वराइजिंग मिल्स, 4/5, इलयूथामुदाली स्ट्रीट, मद्रास-81	बीएचसी धूलन पाउडर— IS : 561-1962	एस ओ 5037 दिनांक 6-11-1971	15-2-1974 के बाद स्थगित
32.	सी एम/एल-2579 9-3-1971	कृषि केमिको, सुन्दर नगर, डाकघर मिठ्ठन-हक, पटना	बीएचसी धूलन पाउडर— IS : 562-1962	एस ओ 2405 दिनांक 19-6-1971	15-3-1974 के बाद स्थगित
33.	सी एम/एल-2597 17-3-1971	आर्यन इंजीनियरिंग एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज, सी-23, 24 इंडस्ट्रियल एरिया, पटना-13	पूर्ण एलुमिनियम चालक और इस्पात प्रबलित एलुमि— नियम चालक— IS : 398-1961	एस ओ 2403 दिनांक 19-6-1971	15-3-1974 के बाद स्थगित
34.	सी एम/एल-2760 13-9-1971	एलाइड इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स, 55-बी, वजीर हसन रोड, लखनऊ-1	डकहरी नाली के पांव से चलने वाले पम्प— IS : 1971-1965	एस ओ 2403 दिनांक 2-9-1972	15-9-1973 के बाद स्थगित
35.	सी एम/एल-2789 28-10-1971	शिवपुर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, तिनग्रह बालीजन रोड, तिनसुखिया (असम)	चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड— IS : 10-1970	एस ओ 1625 दिनांक 8-7-1972	31-10-1973 के बाद स्थगित
36.	सी एम/एल-2815 25-11-1971	मेटल फेब्रीकेटर्स एण्ड प्रिंटर्स, लखानी बीघा, खगूल, पटना (बिहार)	चाय की पेटियो के लिए धातु के फिटिंग— IS :10-1970	एस ओ 403 दिनांक 5-2-1972	30-11-1973 के बाद स्थगित
37.	सी एम/एल-2833 8-12-1971	मणिपुर खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसियेशन (बढ़ई तथा लोहारीयूनिट) महात्मागांधी एवेन्यू, इम्फाल	मधु मक्खियों का छत्ता— IS : 1515-1969	एस ओ 2769 दिनांक 7-10-1972	15-12-1973 के बाद स्थगित
38.	सी एम/एल-2861 31-12-1971	प्रकाश इंजीनियरी कंपनी, मेट्टूपल्लयम रोड, सांईबाबा मिशन डाकघर, कोयम्बटूर-11 (तमिलनाडु)	साफ, ठंड, ताजे पानी के लिए क्षैतिज अपकेन्द्रीय पम्प केवल साइज 65 × 50 मिमी और 65 × 65 मिमी— IS : 1520-1960	एस ओ 2769 दिनांक 7-10-1972	31-12-1973 के बाद स्थगित
39.	सी एम/एल-2916 16-1-1971	हिन्द इनैमल कम्पनी, कायखली डाकघर राजघाट गोपालपुर, 24-परगना	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970	एस ओ 2801 दिनांक 14-10-1972	15-2-1974 के बाद स्थगित
40.	सी एम/एल-3197 27-10-1972	मदारीहाट, वेनियर इंडस्ट्रीज डाकघर, मदारीहाट, जिला जलपायगुड़ी (प. बंगाल)	चाय की पेटियो के लिए प्लाईवुड के तख्ते— IS : 10-1970	एस ओ 846 दिनांक 30-4-1974	31-10-1973 के बाद स्थगित
41.	सी एम/एल-3216 10-11-1972	हीरान स्मालस्कैल इंडस्ट्रीज, 11/5ए बुखाड़ीतल्ला रोड, कलकत्ता-10	खनिको के लिए चमड़े के बचाव बूट और जूते— IS : 1989-1967	एस ओ 1700 दिनांक 16-6-1973	15-11-1973 के बाद स्थागित
42.	सी एम/एल-3254 11-12-1972	मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यू०लि०, 10 जयपुर रोड, दक्षिण दमदम, कलकत्ता-30	तीन फेजी प्रेरण मोटर 0.75 किवा (41 हापा) से 18.5 किवा (25 हा पा) ए श्रेणी के रोधन लगे— IS : 325-1961	एस ओ 1700 दिनांक 16-6-1973	15-12-1973 के बाद स्थगित
43.	सी एम/एल-3281 8-1-1973	कलकत्ता कंटेनर्स एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, 99/4 बी कार्य रोड, कलकत्ता-19	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970	एस ओ 1700 दिनांक 16-6-1973	15-1-1974 के बाद स्थगित

1	2	3	4	5	6
44.	सीएम/एल-3296 9-1-1973	भारत मेटल इंडस्ट्रीज 6 ए, मापगाछी लेन (तिलजला) कलकत्ता-39	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग-- IS : 10-1970	एस ओ 1700 दिनांक 16-6-1973	15-1-1974 के बाद स्थगित
45.	सीएम/एल-3315 31-1-1973	एग्रो केमिकल्स (इंडिया) पटियाला (पंजाब)	मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव-- IS . 2567-1963	,,	31-1-1974 के बाद स्थगित
46.	सीएम/एल-3334 22-2-1973	शारदा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, जैपुर रोड़, जैपुर (असम)	लकड़ी के समतल कपाट (मध्य ठोस भाग) ऊपर प्लाईवुड के तख्ते लगे- IS : 2202 (भाग 1)-1966	एस ओ 1533 दिनांक 26-1973	28-2-1974 के बाद स्थगित
47.	सीएम/एल-3366 21-3-1973	कायन उद्योग, 243, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता-6	18-लीटर समाई वाले-- वर्गाकार टिन- IS : 916-1966	—	15-3-1974 के बाद स्थगित

[सं सीएमडी/12 : 14]

ए० के० गुप्ता, कार्यवाहक महानिदेशक

New Delhi, the 28th January, 1975

S .O. 333. —In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby,, notifies that the certification marks licences, details of which are mentioned in the following schedule, have been deferred after the dates shown against each in column (6):

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date of Issue	Name and Address of the Licensee	Article/Process and the Relevant IS: Designation	S.O. Number and Date of the Gazette Notifying grant of Licence	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L-376 16-1-1962	Surma Valley Saw Mills Pvt. Ltd., P O. Bhangabazar, Distt. Cachar (Assam)	Tea-chest plywood panels IS:10-1970	S.O. 1062 Dated 7-4-1962	Deferred after 31-12-1973
2.	CM/L-480 29-11-1962	Jai Electrical Indz., S/52, Industrial Area, Jullundur City	Metal clad switches, 15 amps, 250 volts with HC and MEM type fuse bases and carriers IS:4064-1967	——	Deferred after 31-1-1974
3.	CM/L-791 30-9-1964	Aluminium Corporation of India Ltd., Jayakayanagar, Near Asansol (West Bengal) Office: 7 Council House Street, Calcutta-1)	AAC & ACSR conductors — IS:398-1961	S.O. 3762 Dated 31-10-1964	Deferred after 15-10-1973
4.	CM/L-1055 20-4-1965	Indian Mineral Industries Limited, Trenching Ground, Approach Road, Alipore, 24 Paragans	BHC dusting powders — IS:561-1962	S.O. 1592 Dated 22-5-1965	Deferred after 15-3-1974
5.	CM/L-1110 8-7-1965	The Aluminium Industries Ltd., Ramchandrapuram, P. O. Hyderabad-32	Polythene insulated and PVC sheathed cables— Is : 1596-1962	S.O. 2667 Dated 28-8-1965	Deferred after 15-11-1973
6.	CM/L-1194 10-1-1966	The Bengal Machinery Co. Pvt Ltd., 9A, Now Tangra Road, Calcutta-46	Flushing cisterns for water closets and urinals— IS:774-1971	S.O. 525 Dated 19-2-1966	Deferred after 15-9-1973
7.	CM/L-1305 28-7-1966	Assam Hardboard Ltd., Panikhaiti (Near Gauhati) Assam (Office: 21-A, Biplabi Rash Behari Road, Calcutta-1)	Fibre normal hard boards— IS:1658-1966	S.O. 2600 Dated 27-8-1966	Deferred after 31-1-1974
8.	CM/L-1403 3-3-1967	Indian Mineral Industries Limited, Trenching Ground, Approach Road, Alipore, 24 Paragans	BHC water dispersible powder concentrates— IS:562-1962	S.O. 1531 Dated 29-4-1967	Deferred after 15-3-1974
9.	CM/L-1624 16-1-1968	M N. Chatterjee & Co., P-48, Benaras Road, Howrah	V-grooved pulley for V-belts- IS:3142-1965	S.O. 684 Dated 24-2-1968	Deferred after . 15-1-1974

1	2	3	4	5	6
10.	CM/L-1813 14-10-1968	Shalimar Biscuits (Pvt) Ltd., Uppal Industrial Estate, Warangal Road, Uppal, Hyderabad-13	Biscuits— IS:1011-1968	S.O. 4257 dated 30-11-1968	Deferred after 15-10-1973
11.	CM/L-1837 20-11-1968	The Aluminium Industries Ltd., Ramchandrapuram, P. O. Hyderabad-32	PVC insulated cables— IS:694 (Pt II)-1964	S.O. 4594 Dated 28-12-1968	Deferred after 15-11-1973
12.	CM/L-1838 20-11-1968	-do-	Thermoplastic insulated weatherproof cables— IS:3035 (Pt II)-1965	S.O. 4594 Dated 28-11-1968	Deferred after 15-11-1973
13.	CM/L-1840 22-11-1968	Indiclay Plot No. 2, Udyog Nagar, Goregaon, Bombay-62	Malathion emulsifiable concentrates— IS:2567-1963	S.O. 4594 Dated 28-12-1968	Deferred after 30-11-1973
14.	CM/L-1843 27-11-1968	-do-	Copper oxychloride water dispersible powder concentrates— IS:1507-1966	-do-	Deferred after 30-11-1973
15.	CM/L-2010 8-7-1969	Shaw Wallace & Co., 84, Industrial Suburb, Yeshwantpur, Bangalore-22	Compounded feeds for cattle— IS:2052-1968	S.O. 3585 Dated 6-9-1969	Deferred after 31-7-1973
16.	CM/L-2075 22-9-1969	Indian Wire & Steel Products, 10, Stark Road, Liluah, Howrah	Mild steel wire for general engineering purposes— IS:280-1972	S.O. 1235 Dated 4-4-1970	Deferred after 28-2-1974
17.	CM/L-2090 30-9-1969	The Industrial Gases Ltd., 146, Andul Road, Howrah-3, (West Bengal) (Office: 15, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-1)	Arc welding transformers— IS: 1851-1966	S.O. 4310 Dated 25-10-1969	Deferred after 30-9-1973
18.	CM/L-2123 27-10-1969	Swastika Steel & Allied Products, 8/1, Nutan Para Road, Liluah, Howrah	Structural steel (ordinary quality)— IS: 1977-1969	S.O. 4849 Dated 6-12-1969	Deferred after 31-10-1973
19.	CM/L-2182 24-12-1969	The Bengal Electric Concern, 33/1, Dinoo Lane, Kadamtalla, Howrah-1	Door closers (hydraulically regulated)— IS: 3564-1970	S.O. 437 Dated 7-2-1970	Deferred after 31-12-1973
20.	CM/L-2356 1-7-1970	K. R. Steel Union P. Ltd., 16-D, Industrial Area, Kalayani, Distt. Nadia (W. Bengal) (Office: 33, Netaji Subhas Road, Calcutta-1)	Cold twisted plain steel bars for concrete reinforcement— IS: 1786-1966	S.O. 2109 Dated 29-5-1971	Deferred after 30-9-1973
21.	CM/L-2403 9-9-1970	Mysore Cements Ltd., Adityapatna, Ammasand P.O., Tumkur Distt. Office: 1 Vidhana Veedhi, Coffee Board Bldgs., (4th Floor), Bangalore-1	Ordinary portland cement— IS: 269-1967	S.O. 3349 Dated 11-9-1971	Deferred after 15-9-1973
22.	CM/L-2420 6-10-1970	Chaliha Rolling Mills Pvt. Ltd., 13, Chanditalla Lane, 55, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Tollygunge, Calcutta-40	Galvanized stay strand— IS: 2141-1968	S.O. 561 Dated 30-1-1971	Deferred after 15-3-1974
23.	CM/L-2436 27-10-1970	The National Insulated Cable Co. of India Ltd., Shamnagar, 24-Parganas, W. Bengal (Office: 'NICCO' House, Hare Street, Calcutta-1)	Flexible cables for miner's cap lamps— IS: 2593-1964	S.O. 561 Dated 30-1-1971	Deferred after 15-11-1973
24.	CM/L-2487 23-12-1970	The Rampur Distillery & Chemical Co. Ltd, Rampur (U.P.)	Rum— IS: 3811-1966	S.O. 2014 Dated 22-5-1971	Deferred after 31-12-1973
25.	CM/L-2488 23-12-1970	Do.	Gin— IS: 4100-1967	S O. 2014 Dated 22-5-1971	Deferred after 31-12-1973
26.	CM/L-2489 23-12-1970	Do.	Whiskies— IS: 4449-1967	S.O. 2014 Dated 22-5-1971	Deferred after 31-12-1973
27.	CM/L-2490 23-12-1970	Do.	Brandies— IS: 4450-1967	S.O. 2014 Dated 22-5-1971	Deferred after 31-12-1973
28.	CM/L-2502 4-1-1971	Nirmal Trading Co., 75, Kashetra Mitra Lane, Salkia (Howrah)	Tea-chest metal fittings— IS: 10-1970	S.O. 5028 6-11-1971	Deferred after 31-12-1973
29	CM/L-2546 18-2-1971	Rattan Re-rollers Pvt. Ltd., 6/1, Kali Majumdar Road, P.O. Ghusuri, Howrah (Office: 23/A, Netaji Subhas Road, Calcutta-1)	Structural steel (standard quality)— IS: 226-1969	S.O. 5037 Dated 6-11-1971	Deferred after 31-8-1973
30.	CM/L-2547 18-2-1971	Do.	Structural steel (ordinary qualtiy)— IS: 1977-1969	S.O.50 37 Dated 6-11-1971	Deferred after 31-8-1973

1	2	3	4	5	6
31.	CM/L-2559 19-2-1971	Bhuvaneshwari Pulverising Mills, 4/5, Elaya Mudali Street, Madras-81	BHC dusting powders— IS: 561-1962	S.O. 5037 Dated 6-11-1971	Deferred after 15-2-1974
32.	CM/L-2579 9-3-1971	Krishi Chemico, Sunder Nagar, P.O. Mittanhak, Patna	BHC dusting powders— IS: 562-1962	S.O. 2405 Dated 19-6-1971	Deferred after 15-3-1974
33.	CM/L-2597 17-3-1971	Aryan Engineering & Allied Industries, C-23, & 24 Industrial Area, Patna-13	All aluminium conductors and ACSR conductors— IS: 398-1961	S.O. 2405 Dated 19-6-1971	Deferred after 15-3-1974
34.	CM/L-2760 13-9-1971	Allied Industrial Traders, 55-B, Wazir Hasan Road, Lucknow-1	Single-barrel stirrup-pump— IS: 1971-1965	S.O. 2403 Dated 2-9-1972	Deferred after 15-9-1973
35.	CM/L-2789 28-10-1971	Sewpur Iron & Steel Works, Tingrai Balizan Road, Tinsukia (Assam)	Tea-chest plywood— IS: 10-1970	S.O. 1625 Dated 8-7-1972	Deferred after 31-10-1973
36.	CM/L-2815 25-11-1971	Metal Fabricaters & Printers, Lakhani Bigha, Khagul, Patna (Bihar)	Tea-chest metal fittings— IS: 10-1970	S.O. 403 Dated 5-2-1972	Deferred after 30-11-1973
37.	CM/L-2833 8-12-1971	Manipur Khadi & Village Industries Association (Carpentry & Blacksmithry Unit), Mahatma Gandhi Avenue, Imphal	Beehieves— IS: 1515-1969	S.O. 2769 Dated 7-10-1972	Deferred after 15-12-1973
38.	CM/L-2861 31-12-1971	Prakash Engg. Co., Mettupalayam Road, Saibaba Mission P.O., Coimbatore-11 (Tamil Nadu)	Horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water, sizes 65 x 50 mm and 75 x 65 mm only— IS: 1520-1960	S.O. 2769 Dated 7-10-1972	Deferred after 3 -12-1973
39.	CM/L-2916 16-2-1972	Hind Enamel Company, Kaikhali, P.O. Rajarghat, Gopalpur, 24-Parganas	Tea-chest metal fittings— IS: 10-1970	S.O. 2801 Dated 14-10-1972	Deferred after 15-2-1974
40.	CM/L-3197 27-10-1972	Madarihat Veneer Industries, P.O. Madarihat, Distt. Jalpaiguri (WB)	Tea-chest plywood panels— IS: 10-1970	S.O. 846 Dated 30-3-1974	Deferred after 31-10-1973
41.	CM/L-3216 10-11-1972	Hiron Small Scale Inds., 1/5A, Burwaritala Road, Calcutta-10	Miner's safety leather boots and shoes— IS: 1989-1967	S.O. 1700 Dated 16-6-1973	Deferred after 15-11-1973
42.	CM/L-3254 11-12-1972	Motor & Machinery Manufacturers Ltd., 10, Jawpur Road, South Dum Dum, Calcutta-30	Three phase induction motors from 0.75 kW (1 HP) upto 18.5 kW (25 HP) with class 'A' insulation— IS: 325-1961	—	Deferred after 15-12-1973
43.	CM/L-3281 8-1-1973	Calcutta Containers & Printing Works, 99/4D, Karya Road, Calcutta-19	Tea-chest metal fittings— IS: 10-1970	—	Deferred after 15-1-1974
44.	CM/L-3296 9-1-1973	Bharat Metal Industries, 6A, Sapagachi Lane, (Tiljala), Calcutta-39	Tea-chest metal fittings— IS: 10-1970	—	Deferred after 15-1-1974
45.	CM/L-3315 31-1-1973	Agro Chemicals (India), Patiala (Punjab)	Malathion emulsifiable concentrates— IS: 2567-1963	—	Deferred after 31-1-1974
46.	CM/L-3334 22-2-1973	Sarda Plywood Industries (P) Ltd., Jeypore Road, Jeypore (Assam)	Wooden flush door shutters (solid core Type), with plywood face panels— IS: 2202 (Pt. I)-1966	S.O. 1553 Dated 2-6-1973	Deferred after 28-2-1974
47.	CM/L-3366 21-3-1973	Kayan Udyog, 243 Acharya Parafulla Chandra Road, Calcutta-6	18-litre square tins— IS: 916-1966	—	Deferred after 15-3-1974

[No. CMD/13 : 14]

A. K. GUPTA, Acting Director General.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
(पैट्रोलियम विभाग)
नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1975

का० आ० 334.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में व्यधन स्थल संख्या कलोल 7 से जी० जी० एस०-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है।

और यतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 6-12-73 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है।

अब अतः पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

अनुसूची

कलोल 55 से जी जी० एस० तक पाईपलाइन की सक्रिया का पर्यावसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	सक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	सेर्था	1567	22-6-74	6-12-1974

[संख्या 12016/4/74-एल० एंड एल०/4]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS
(Department of Petroleum)
New Delhi, the 24th January, 1975

S.O. 334.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site No. Kalol-7 to GGS-I in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 6-12 73

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from Kalol-7 to GGS-I

Name of Ministry	Village	S.O.No.	Date of publication in the gazette of India.	Date of termination of operation.
Petroleum & Chemicals	Sertha	1567	22-6-74	6-12-73

[No. 12016/4/74-L&L/IV]

का० आ० 335.—यतः उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में व्यधन स्थल संख्या कलोल 17 और 110 से सी० टी० एफ० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है।

और यतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 19-6-1973 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है।

अब अतः पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

अनुसूची

कलोल 17 और 110 से सी० टी० एफ

मंत्रालय का नाम	गाव	सर्वेक्षण सख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	सक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	धनाज	1394	8-6-1974	19-6-1973

[संख्या 12016/4/74-एल० एंड एल/3]

S.O.335.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act,1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appened thereto for the transport of Petroleum from drill site No. Kalol-17&110 to C.T.F. in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 19-6-73

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules, 1963, the Compoetent Authority notified the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Kalol-17 & 110 to C.T.F.

Name of Ministry	Village	S.O.No.	Date of publication in the gazette of India.	Date of termination of operation.
Petroleum & Chemicals	Dhanaj	1394	8-6-74	19-6-73

[No. 12016/4/74L&L/III]

का० आ० 336.—यत: इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में व्यधन स्थल संख्या सानद 29 से जी० जी० एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है।

और यत: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 19-9-1972 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है।

अब अत: पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

अनुसूची

सानन्द 29 से जी० जी० एस० तक पाईपलाइन की संक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गाव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	संक्रिया पर्यवसान की तारीख
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	भीमासान हाजीपूर थौल	1570	22-6-74	19-9-1972

[संख्या 12016/4/74-एल० एड एल०/2]

S.O.336.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appened thereto for the transport of Petroleum from drill site No. San and 29 to GGS in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 19-9-72.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Sanand 29 to GGS

Name of Ministry	Village	S.O.No.	Date of publication in the gazette of India.	Date of termination of operation.
Petroleum & Chemicals	Bhimasan Hajipur Thol	1570	22-6-74	19-9-72

[No. 12016/4/74-L&L/II

का० आ० 337.—यत इस सलग्न अनुसूची म विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र मे व्यधाधान स्थल सख्या कलोल-55 से जी० जी० एस०-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये उस सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है।

और यत: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 6-12-73 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खड (1) मे निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है।

अब अत पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकारो का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट सक्रिया के पर्यवसान के रूप मे एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

अनुसूची

कलोल 55 से जी० जी० एस० 1 तक पाईपलाइन की सक्रिया का पर्यवसान

मत्रालय का नाम	गाव	सर्वेक्षण सख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	सक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पैट्रोलियम और रसायन मत्रालय	सैर्था	1571	22-6-74	6-12-73

सख्या 12016/4/74-एल० एक्स० एल०/1
के० पी० देशपाडे,
गुजरात के लिये अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S. O. 337.—WHEREAS by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisitionof Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site No. Kalol-55 to G G.S I in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 6-12-73

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation referred to above

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Kalol-55 to G.G S. I

Name of Ministry	Village	S.O.No.	Date of publication in the gazette of India.	Date of termination of operation.
Petroleum & Chemicals	Sertha	1571	22-6-74	6-12-73

[No. 12016/4/74-LXL/I]
K. P. Deshpandey
Incharge Competent Authority under the act for Gujarat

नौवहन और परिवहन मत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1975

का० आ० 338.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा श्री निहाल सिह, नगर पारषद् को स्व० श्री बलराज खन्ना के स्थान पर दिल्ली परिवहन निगम के सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार नौवहन और परिवहन मत्रालय की अधिसूचना स० सा०आ० 255(ई) दिनाक 2-5-1973 73 मे निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना मे मद (11) तथा तत्सबधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् —

"(11) श्री निहाल सिह
नगर पारषद"

[स० 15-टी०ए०जी०(35)/72]
एन० ए० ए० नारायणन अवर सचिव,

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 16th January, 1975

S.O. 338.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Nihal Singh, Municipal Councillor, as a Member of the Delhi Transport Corporation vice late Shri Balraj Khanna and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O 255(E), dated the 2nd May, 1973, namely :—

In the said notification, for iteem (xi) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(xi) Shri Nihal Singh,
Municipal Councillor".

[No. 15-TAG(35)/73]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1975

का० आ० 339.—सर्व साधारण की सूचना के लिये यह एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने श्री ए० एस० एन० अय्यर, लेखा अधिकारी, दिल्ली परिवहन निगम को छुट्टी पर गये श्री के० एन० सहगल के स्थान पर 18 नवम्बर, 1974 से 2 जनवरी, 1975 तक दिल्ली परिवहन निगम के मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त किया है।

[सं० 1-टी० ए० जी० (28)/74]

एन० ए० ए० नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 1975

S.O. 339.—It is hereby published for the information of public that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government have appointed Shri A. S. N. Iyer, Accounts Officer, Delhi Transport Corporation as Chief Accounts Officer of the Delhi Transport Corporation with effect from the 18th November, 1974 to the 2nd January, 1975, vice Shri K. N. Saigal, proceeded on leave.

[No 1-TAG(28)/74]

N. A. A. NARAYANAN, Under Secy

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1971

का० आ० 340—यत: कान्डला अरजिस्ट्रीकृत कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 का संशोधन करने के लिये प्रारूप स्कीम, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 2303 तारीख 28 अगस्त, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7 सितम्बर, 1974 के पृष्ठ सं० 2445 पर प्रकाशित की गई थी,

और यत: उक्त राजपत्र जनता को 7 सितम्बर, 1974 को उपलब्ध करा दिया गया था,

और यत: केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुये है,

अत: अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कान्डला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस स्कीम का नाम कान्डला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) द्वितीय संशोधन स्कीम 1975 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2 कान्डला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खंड 20 में 'स्पष्टीकरण' के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस खंड मे एक दिन से किसी भी दिन को कर्मकार द्वारा की गई एक या एक से अधिक पारी अभिप्रेत है।"

[फा० सं० एस० 70012/10/73-पी० एंड डी०/ एल० डी०]

New Delhi, the 21st January, 1975

S.O. 340.—Whereas certain draft scheme to amend the Khandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1968 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment Act, 1948 (9 of 1948) at page 2445 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 7th September, 1974 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2303, dated the 28th August, 1974 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 7th September, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme. 1968, namely:

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Second Amendment Scheme, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2 In clause 20 of the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 for the "Explanation", the following Explanation shall be substituted, namely:—

"Explanation.—In this clause, a 'day' means one or more than one shift worked by a worker on any day."

[F. No. S-70012/10/73-P&D/LD]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1975

का० आ० 341—कान्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त उपधारा की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

ऐसे किन्ही भी आक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्कीम का प्रारूप

1 इस स्कीम का नाम कान्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1975 है।

2 कान्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 के खण्ड 16 में, अंक "8" के स्थान पर, अंक "13" रखा जाएगा।

[फाइल सं० 70012/5/74-पी डी/एल डी]

वी० शंकरलिंगम अवर सचिव

New Delhi, the 24th January, 1975

S.O. 341.—The following draft of a Scheme further to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1975.

2. In clause 36 of the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, for the figure "8", the figure "13" shall be substituted.

[File No. S. 70012/5/74-PD/LD]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1975

का० आ० 342.—अधिसूचना संख्या सेक्रट्री [बी एंड सी-26/67 दिनांक 13/9/1967 में आंशिक संशोधन के विषय में दिल्ली विकास प्राधिकरण एक्ट 1957 के सैक्शन 5 के अन्तर्गत मास्टर प्लान तैयार करने और अन्य दूसरी योजनाओं के विकास से संबंधित कार्यों के लिये या तत्संबंधी अन्य कार्यों के लिए उपर्युक्त एक्ट के प्रशासन के संबंध मे दिल्ली विकास सलाहकार समिति को प्राधिकरण के लिये सलाह देने के कार्य के लिये अधिसूचित किया गया था उसी में आगे यह भी सूचित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश त्यागी, सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत व्यवस्था के अनुसार चार वर्ष के लिए दिनांक 13 मई, 1974 से डा० भाई महावीर के स्थानापन्न होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुन लिये गये है ।

[स० सेक्रे०/बी एंड सी/26/67]

एच० एन० फोतेदार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 28th January, 1975

S.O. 342.—In partial modification of Notification No. Secy/V&C/26/67, dated 13th September 1967, issued in pursuance of the provisions of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957, in which the constitution of the Advisory Council by the Delhi Development Authority was notified for the purpose of advising the Authority on the preparation of the Master Plan and on such other matters relating to the planning of development of arising out of, or in connection with the administration of the said Act, as may be referred to it by the Authority, it is further notified that Shri Om Parkash Tyagi, Member, Rajya Sabha has been elected w.e.f. 13th May, 1974 as a member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years subject to the other provisions of the Delhi Development Act, 1957, vice Dr. Bhai Mahavir.

[No. Secy./V&C/26/67]

H. N. FOTEDAR, Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1975

का० आ० 343.—राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ब) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री कृष्ण चन्द्र को राजघाट समाधि समिति का शासकीय सदस्य नियुक्त करती है, और उन्हे श्री बालेश्वर प्रसाद के स्थान पर, उक्त समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० 19/2/62-डब्ल्यू०-1, तारीख 22 अगस्त, 1962 मे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्.—

उक्त अधिसूचना में आने वाले शब्दों "श्री बालेश्वर प्रसाद" के स्थान पर दोनों स्थानो पर जहां भी वे आये हैं, "श्री कृष्ण चन्द", शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 25012(3)/72-डब्ल्यू०-3]

राम लुभाया अहलूवालिया, उप सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Works Division)

New Delhi, the 14th January, 1975

S.O. 343.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) and Sub-section (2) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (4 of 1951), the Central Government hereby nominates Shri Krishan Chand, Lt. Governor of Delhi, to be an official member of the Rajghat Samadhi Committee and also appoints him as the Chairman of the said Committee vice Shri Baleshwar Prasad, and hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 19/2/62-WI, dated the 22nd August, 1962, namely :—

In the said notification, for the words "Shri Baleshwar Prasad" in both the places where they occur, the following words shall be substituted, namely :—

"Shri Krishan Chand".

[No. 25012(3)/72-W-III]

R. L. AHLUWALIA, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

का० आ० 344.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, जरखी दादरी के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री ओ० पी० शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय फरीदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है

अनुसूची

क्या मैसर्स डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड, चरखी दादरी के प्रबन्धतन्त्र की, 11 जनवरी, 1974 से श्री लाल सिंह, लिपिक, की सेवायें समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

[संख्या एल०-29012/20/74-एल० आर०-4]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1974

S.O. 344.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri O. P. Sharma as Presiding Officer with headquarters at Faridabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri in terminating the services of Shri Lal Singh, Clerk, with effect from the 11th January, 1974 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-29012/20/74-LR IV]

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1974

का० आ० 345.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सोन वैली पोर्ट लैण्ड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड की चूना-पत्थर खान, डाकघर बौलिया, जिला रोहतास के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सोन वैली पोर्टलैण्ड सीमेण्ट कम्पनी, लिमिटेड की चूना पत्थर खान, डाकघर बौलिया, जिला रोहतास के कर्मकारों की, दूसरे सीमेंट मजदूरी बोर्ड तथा रेड्डी पंचाट की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अन्तरिम सहायता की मंजूरी की मांग न्यायोचित है? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं?

[संख्या एल०-29011(57)/74-एल०आर०-4]

New Delhi, the 17th December, 1974

S.O. 345.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Limestone Quarry of Sone Vallery Port Land Cement Company Limited Post Office Baulia, District Rohtas and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen of the Limestone Quarry of the Sone Vallery Port Land Cement Company Limited, Post Office, Baulia, District Rohtas for implementation of the recomendations of the Second Cement Wage Board and the Reddy Award and the grant of interim relief is justified? If so, to what relief and from what date are the workmen entitled?

[No. L-29011(57)/74-LR IV]

का० आ० 346.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में इंडिया सीमेण्ट लिमिटेड, सकारी के खनन ठेकेदार—मैसर्स स्टार कन्स्ट्रक्शन एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, सकारी, के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरु टी० पलानीअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

'वर्ष 1973-74 के लिए कर्मचारियों को देय बोनस की मात्रा'

[संख्या एल०-29011(76)/74-एल०आर०-4]

S.O. 346.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs. Star Construction and Transport Company, Sankari, Mining Contractors to the India Cement Limited, Sankari and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Thiru T. Palaniappan as Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Quantum of bonus payable to the employees for the year 1973-74."

[No. L-29011(76)/74-I.R IV]

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1975

का० आ० 347.—यत० केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत. केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, रायपुर के प्रबन्धतन्त्र की श्री सतीश कुमार झा, चपरासी की सेवायें 11 मई, 1973 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है?

[स० एल० 12012/16/74-एल० आर० 3]

New Delhi, the 7th January, 1975

S.O. 347.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

THE SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Bank of India, Raipur in terminating the service of Shri Satish Kumar Jha, Peon, with effect from the 11th May, 1973 is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. L. 12012/16/74/LRIII]

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1975

का० आ० 348.—यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोढी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है;

अनुसूची

क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ में टंकक श्री एस० पी० शर्मा, अपनी आरम्भिक नियुक्ति की तारीख से लिपिक एवं टंकक के रूप में पुनः पदानिहित किये जाने के हकदार हैं? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है?

[स० एल० 12012/127/73-एल० आर० 3]

ORDER

New Delhi, the 15th January, 1975

S.O. 348.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexd;

And, whereas the Central Government cosiders it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal

SCHEDULE

Whether Shri S. P. Sharma, Typist in the Central Bank of India, Chandigarh, is entitled to be re-designated as Clerk-cum-Typist with effect from the date of his initial appointment? If not, to what relief is he entitled?

[No L. 12012/127/73-LRIII]

नई दिल्ली 17जनवरी, 1974

का० आ० 349.—यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता का श्री राम लाल टण्डन, लिपिक के कर्तव्यों का पालन करता रहा है? यदि हां, तो क्या उसे लिपिक के रूप में पदावनिहित किया जाना चाहिये और उसका नाम लिपिकों की ज्येष्ठता सूची में लाया जाना चाहिये, और किस तारीख से?

[सं० एल०-12012/131/74-एल० आर० III]

New Delhi, the 17th January, 1975

S.O. 349.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Hindustan Commercial Bank Limited, and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether Shri Ram Lal Tandon of Hindustan Commercial Bank Limited Calcutta, has been performing the duties of a clerk? If so, should he be designated as clerk and his name be brought on the seniority list of the clerks and from what date?

[No. L. 12012/131/74/I R III]

का० आ० 350.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान

और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अत अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतन्त्र का, श्री जे० डी० जैन, मेरठ शाखा के कैशियर को, 22 दिसम्बर, 1973 से सेवान्मुक्त करना न्यायोचित है? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल०-12012/76/74-एल० आर० 3]

S.O. 350.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

In the management of State Bank of India justified in discharging from service Shri J. D. Jain, Cashier of Meerut Branch, with effect from the 22nd December, 1973? If not to what relief is he entitled?

[No. L. 12012/76/74-LR. III]

का० आ० 351.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अत, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया, आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र की श्री मोहनराम की सेवाओं को 2 जुलाई, 1974 से समाप्त कर देने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/33/74-एल०आर०3]

S.O. 351.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the United Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the United Bank of India, Asaf Ali Road, New Delhi in terminating the services of Shri Mohan Ram with effect from the 2nd July 1974 is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. L. 12012/33/74-I R. III]

का० आ० 352.—अतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस०एच०जे० नकवी होंगे जिनका मुख्यालय कानपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतन्त्र की, अपनी वाराणसी शाखा के के श्री एन०एन० भंडारी, लिपिक को विशेष सहायक के स्थानापन्न स्थायी अवसर देने से इंकार करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/65/74-एल०आर० 3]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

S.O. 352.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed:

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. H. J. Naqvi shall be the presiding Officer, with headquarters at Kanpur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Baroda in denying officiating permanent chances of Special Assistant to Shri N. N. Bhandari, Clerk in their Varanasi Branch is justified? If not, to what relief is he entitled ?

[No. L. 12012/65/74-LR.III]

New Delhi, the 27th January, 1975

S.O. 353.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Rajasthan Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th January, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT-7 of 1972

Ref.—Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, New Delhi Order No. L-12012/10/72-LRIII dated 15th June, 1972.

In the Matter of an Industrial Dispute,

BETWEEN

The All India Punjab National Bank Employees Association, Delhi.

AND

The Punjab National Bank, Central Circle, Indore.

APPEARANCES :

For the Association—Shri C. L. Bharadwaj.

For the Management—Shri R. P. Raizada.

Date of Award—16th December, 1974

AWARD

The Central Government has made the following reference to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Indore in denying officiating chances in clerical cadre to Shri Anand Singh, Peon, Branch Office, Jaipur from September, 1971 onwards is justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

The statement of claim was filed by the Association of the Punjab National Bank Employees Union, Rajasthan State on behalf of the worker. The facts, as stated in the statement of claim, are not denied. The contention on behalf of the management is that Shri Anand Singh, Peon was allowed to officiate as a Clerk for the periods mentioned in the statement of claim, but this was wrongly done because the authorities concerned did not interpret the circular of the bank correctly. According to the circular, which is marked Ex. W-1, officiating chance in clerical cadre was to be given to those Peons more than four years service after matriculation. Shri Anand Singh had not put in four years service after matriculation when he was given officiating chances. Later on when attention was drawn to the interpretation of the circular, no chance was given to Shri Anand Singh.

I have gone through the wordings of the circular Ex. W-1 and consider that it does not mean that the incombent should put in four years service after matriculation. Therefore, in my opinion the management was not justified to stop giving officiating chances to Shri Anand Singh on this ground. But giving officiating chances to higher post is entirely the discretion and function of the management. A workman cannot claim promotion as of right unless he has been deprived of the promotion or the officiating chance on account of victimization or unfair labour practice. In this case the association has not been able to establish that the management has victimized the workman or had adopted unfair labour practice. The workman could not take this plea because he was given officiating chances for years and when he had put in four years service after matriculation, he was again given the chance. If the management had stopped giving officiating chances to Shri Anand Singh for the sake of victimization, then they could still refuse to do so, even when he had put in four years service after matriculation. In view of the fact that promotion or giving officiating chance to higher post is the function of the management, it will not be proper for this Tribunal to interfere in the matter. As observed above, the Tribunal could interfere only when victimization or unfair labour practice had been proved. The reference is answered accordingly.

U. N. MATHUR, Judge,

Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur

[No. L-2012/10/72-LR.III]

S.O. 354.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Rajasthan Limited, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th January, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT-10 of 1972

Ref:—Government of India, Ministry of Labour & Employment, Labour & Rehabilitation, Department of Labour & Employment, New Delhi Order No. L. 12012/114/74-LR-III dated 2nd November, 1972.

In the Matter of an Industrial Dispute.

BETWEEN

The Rajasthan State Bank Workers Association, Ajmer.

AND

The Rajasthan Bank Limited, Johri Bazar, Jaipur.

APPEARANCES :

For the Union.—Shri C. L. Bhardwaj.

For the Management.—Shri M. M. Seth.

Date of Award: 16th December, 1974.

AWARD

The Central Government has made the following reference to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Bank of Rajasthan Limited, Jaipur in denying Head Clerk's Allowance to Shri Babulal Choudhaury with effect from the 27th December, 1971 is justified ? If not, to what relief is he entitled?"

The statement of claim was filed by the Rajasthan State Bank and Workers Organization on behalf of the workman. The admitted facts are that Shri Babulal was a clerk at the Central Office of the Rajasthan Bank at Jaipur. He was a confirmed Head Clerk and was paid Rs. 20 p.m. as Special Allowance for the post. On 13-2-67 Shri Babulal was transferred to Sri Ganganagar as Head Clerk. On 13-3-68, he was again transferred to the Central Office, Jaipur on his own request and on the condition that as there was no vacancy of Head Clerk at the Central Office, Jaipur he would work as a Clerk and not claim Special Allowance of the post of Head Clerk. On 16-10-71 the bank management gave him chance of Head Clerk on the occurrence of the vacancy and the Special Allowance was allowed to him. On 20-12-71, the management stopped his allowance of the post of Head Clerk on the pretext that the All India Bank of Rajasthan Coordination Committee had objected to the allowance. The bank Workers Organisation has, therefore, taken up the matter claiming the Special allowance of the post with effect from 20-12-71, since when it was stopped.

In reply the management admitted all the facts and pleaded that because of the objection raised by the Coordination Committee, the allowance was stopped.

Evidence of the parties was recorded. The only point for consideration is whether the action of the management for stopping the Special Allowance of the post of Head Clerk to Shri Babulal on the plea that it was objected to by the Coordination Committee was justified. It is true that when Shri Babulal got himself transferred to Jaipur from Sri Ganganagar, he accepted the condition put by the management that since there was no vacancy to the post of Head Clerk in Jaipur, he could be transferred as a Clerk and no special allowance would be given to him. It is because of this acceptance of the condition that the workman has not claimed any allowance for the period, he worked as an ordinary clerk before 16-10-71. On 16-10-71 the management found to the post of Head Clerk and Shri Babulal was given the chance. That means that the condition which was put by the management earlier was no more in the way to his promotion. There occurred a vacancy of the post of Head Clerk in Jaipur and since Shri Babulal was a confirmed Head Clerk, he was rightly given the chance. Now when he was working as Head Clerk, there was no justification in reverting him to the post of Clerk. It is submitted on behalf of the management that the Coordination Committee examined his case as an ordinary clerk vis-a-vis other clerks. But this action was not legal and proper, because Shri Babulal could not be considered along with ordinary clerks. He was a confirmed Head Clerk but because of certain family circumstances he accepted to work as an ordinary clerk so that he could be posted in Jaipur. Simply because he was working as a Clerk due to certain circumstances, it does not mean that he was not a confirmed Head Clerk and he could not be considered along with other ordinary clerks. In my opinion, therefore, there was no justification in stopping the Special Allowance allowed to Shri Babulal for his working as Head Clerk with effect from 16-10-71. He is entitled to the Special Allowance with effect from 16-10-71. The reference is answered accordingly.

U. N. MATHUR, Presiding Officer,

[No. L. 12012/114/72-LR.-III]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1975

का० आ० 355.—यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री इन्द्रजीत जी० ठाकुर, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के समक्ष लम्बित है ;

और यतः श्री इन्द्रजीत जी० ठाकुर की सेवायें अब उपलब्ध नहीं रही;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद से संबद्ध कार्यवाहियों को श्री इन्द्रजीत जी० ठाकुर से वापस लेती है और उसे, उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, मुम्बई को उक्त कार्यवाहियों के निपटान के लिए इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण कार्यवाहियों नये सिरे से आरम्भ करेगा और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	विवाद का पक्षकार	औद्योगिक अधिकरण को निर्देश की संख्या और तारीख
1.	काण्डला स्टेवेडोर्स एसोसियेशन लिमिटेड, न्यू काण्डला और उनके कर्मकार ।	भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 (ii) में प्रकाशित संख्या एस-37011/3/71-पी० एण्ड डी०, तारीख 9 मार्च, 1972, देखिये का० आ० संख्या 1237, तारीख 20 मई, 1972 ।

[संख्या एस-37011/3/71-पी० एण्ड डी०/सी०एम०टी०/डी०-4(ए)]

ORDERS

New Delhi, the 8th January, 1975

S.O. 355.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri Indrajit G. Thakore, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Ahmedabad;

And whereas, the services of Shri Indrajit G. Thakore have ceased to be available:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 and section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Shri Indrajit G. Thakore and transfers the same to the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, constituted under section 7A of the said Act, for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings de novo and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute.	No and date of reference to the Indstrial Tribural
1.	Kandla Stevedores Association Limited, New Kandla and their workmen.	No. L. 37011-3-71-P&D, dated the 9th March, 1972 published in the Gazette of India Part II, Section 3 (ii) Vide S. O. No. 1237, dated the 20th May, 1972.

[No. L-37011/3/71-P&D/CMT/D. IV(A)]

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1975

का० आ० 356.—यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स आरमैन ज्यार्जे एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिय निदशित करना वांछनीय समझती है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स आरमैन ज्यार्ज एड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, के अधीन नियोजित श्री संतोष कुमार मुखर्जी, जेट्टी लिपिक, की सेवाओं का 19-7-1974 से पर्यवसान करना न्यायोचित है ? यदि नही तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-32012/19/74-पी० एण्ड डी०/ सी० एम० टी०/डी०-4(ए०)]

नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

New Delhi, the 25th January, 1975

S.O. 356.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs. Armen George and Company (Private) Limited, Calcutta and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the termination of services of Shri Santosh Kumar Mukherjee, 'Zetty Clerk' employed under Messrs. Armen George and Company (Private) Limited from 19-7-1974 is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. L-32012/19/74-P&D/CMT/D-IV(A)]

NAND LAL, Section Officer (Special)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1974

का० आ० 357.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे मे मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड की श्री लखिमाता कोइलियरी डाकघर निर्साचट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्ध तन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्याय निर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड, की श्री लखिमाता कोइलियरी, डाकघर निर्साचट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र की, श्री दिलीप कुमार गोरे लिपिक को, मार्च, 1973 से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नही, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-2012/35/74-एल०आर०-2]

New Delhi, the 18th December, 1974

S.O. 357.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sree Lakhimata Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govern-

ment hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Sree Lakhimata Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad in stopping Shri Dilip Kumar Gorai, Clerk from work with effect from March, 1973 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L-19012/15/73-LR. II]

नई दिल्ली दिसम्बर, 1974

का०आ० 358—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड की राज कोलियरी, डाकघर मुगमा, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम, की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड की राज कोलियरी, डाकघर, मुगमा, जिला धनबाद, के प्रबन्धतन्त्र की, सर्वश्री मुक्तिआदा दास, शाट फायरर कुली और गुन्देन्द्रा नाथ डे, लोडिंग-सुपरवाइजर की क्रमशः 26 फरवरी, 1973 और 12 फरवरी, 1973 से सेवायें रोकने की कार्रवाई न्यायोचित हैं ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सख्या एल०-2012/168/73-एल०आर०-2]

New Delhi, the 18th December, 1974

S.O. 358.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Raj Colliery of Messrs. Coal Mines Authority Limited, Post Office Mugma, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Raj Colliery of Coal Mines Authority Limited, Post Office Mugma, District Dhanbad, in stopping the services of Sarvashri Muktiaada Das, Shotfirer Cooly, and Gundendra Nath Dey, Loading Supervisor with effect from the 26th February, 1973 and the 12th February, 1973 respectively is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

[No. L-2012/168/73-LR. II]

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1975

का०आ० 359—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिलेक्टिड सामला कोइलियरी, डाकघर, पांडवेश्वर, जिला बर्दवान के प्रबन्ध तन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्याय निर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिलेक्टिड सामला कोइलियरी, डाकघर पांडवेश्वर, जिला बर्दवान के सम्बन्ध में प्रबन्धतन्त्र का, सर्वश्री सुखन अहीर, मशीन मजदूर और रामाशीष सिंह, लाइन मिस्त्री को 8 अगस्त, 1972 से पदच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-19012/15/73-एल०आर०-2]

New Delhi, the 1st January, 1975

S.O. 359.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Selected Samla Colliery, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management in relation to Selected Samla Colliery, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan is justified in dismissing Sarva Shri Sukhan Ahir, Machine Mazdoor and Ramashis Singh Line Mistry with effect from the 8th August, 1972? If not, to what relief are the workmen entitled?

[No. L-19012/15/73-LRII.]

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1975

का०आ० 360—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिलेक्टिड सामला कोइलियरी, डाकघर पांडवेश्वर, जिला बर्दवान के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यानिर्णयय के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिलेक्टेड सामला कोलियरी, डाकघर पांडवेश्वर, जिला बर्दवान से सम्बद्ध प्रबन्धतन्त्र का, सर्वश्री सुदामा अहीर और रामबिहारी जादव, ट्रैमरों को, 2 अगस्त, 1972 से पच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्याएल०-19012/17/73-एल०आर०-2]

New Delhi, the 2nd January, 1975

S.O. 360.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Selected Samla Colliery, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication, to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management in relation to Selected Samla Colliery, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan, is justified in dismissing Sarvashri Sudama Ahir, and Rambehari Jadab, trammers with effect from the 2nd August, 1972? If not, to what relief are the workmen entitled?

[No. L-19012/17/73-LRII]

का०आ० 361—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड डाकघर निर्सा चट्टी, जिला धनबाद के अधीन क्षेत्र संख्या 6 की कोयला खानों, के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या यूनियन, अर्थात् बिहार कोलियरी कामगार यूनियन का, कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड डाकघर निर्सा चट्टी, जिला धनबाद के अधीन क्षेत्र संख्या 6 की कोयला खानों के कर्मकारों को कोयला खनन उद्योग में मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार हाजिरी के अनुसार परिवर्ती महंगाई भत्ते के संदाय का दावा न्यायोचित है ?

यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से ?

[संख्या एल-2012/162/73-एल०आर०-2

S.O. 361.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Collieries of Area No. 6 under the Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Wheher the claim of the Union namely Bihar Colliery Kamgar Union for payment of Variable Dearness Allowance as per attendance to the workmen of the collieries of Area No. 6 under the Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad as per recommendations of the Wage Board is Coal Mining Industry is justified? If so, to what relief are the workmen entitled and from what date?

[No. 2012/162/73-LR. II]

का० आ० 362—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिलेक्टिड सामला कोलियरी, डाकघर, पांडवेश्वर, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिलेक्टिड सामला कोलियरी, डाकघर, पाडवेश्वर, जिला बर्दवान से सम्बद्ध प्रबन्धतन्त्र की सर्वश्री देवसागर अहीर, पम्प खलासी, (2) लक्ष्मण अहीर, प्रॉप० मजदूर, (3) जगनूगोप, प्रो प० मिस्त्री, (4) इन्द्रदेव चौधरी, चपरासी, (5) सुचितसिंह, ट्रैमर, (6) शिवचरण शाव, प्रोप० मजदूर, (7) गोरख सिंह, ट्रैमर, (8) रामजी जावव, प्रॉप० मजदूर, (9) ललन सिंह, मशीन चालक, (10) शम्भुसिंह, प्राप मजदूर (11) भीम जावव, प्रॉप मजदूर, (12) बिशनदेव अहीर, ट्रैमर (13) पचदेवसिंह, लाइन मजदूर, (14) बच्चूरामसिंह, ट्रैमर, (15) बोधन अहीर, शॉटफायरर, (16) रासबिहारीसिंह, ट्रैमर, (17) फजल करीम, लैम्प इस्यूअर, (18) महेन्द्र अहीर, चपरासी, (19) रामपति रोथ, ट्रेमर, (20) अलक अहिर, मशीन मजदूर और (21) नागेश्वर सिंह चपरासी को 25 जुलाई, 1972 से पदच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल० -19012/16/73-एल०आर०-2]

S.O. 362.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Selected Samla Colliery, Post Office andaveshwar, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management in relation to Selected Samla Colliery, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan, is justified in dismissing Sarvashri Debsagar Ahir, Pump Khalasi, (2) Lachmon Ahir, Prop Mazdoor, (3) Jagnu Gope, Prop. Mistry, (4) Indradeb Choudhury, Chaprasi, (5) Suchit Singh, Trammer, (6) Seocharan Show, Prop. Mazdoor, (7) Gorakh Singh, Trammer, (8) Ramji Jadab, Prop. Mazdoor, (9) Lalan Singh, Machine Driver, (10) Shambhu Singh, Prop. Mazdoor, (11) Bhim Jadab, Prop. Mazdoor, (12) Bishendeo Ahir Trammer, (13)

Pachdee Singh, Line Mazdoor, (14) Bachuram Singh, Trammer, (15) Bodan, Ahir Shot Firera (16) Rasbehari Singh, Trammer, (17) Fajal Karim, Lamp Issuer, (18) Mohendar Ahir, Chaprasi, (19) Rampati Routh, Trammer, (20) Jhalak Ahir, Machine Mazdoor and (21) Nageswar Singh, Chaprasi, with effect from the 25th July, 1972? If not, to what relief are the workmen entitled?

[No. L-19012/16/73-LRII]

LALFAK ZUALA, Dv. Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1975

का०आ० 363.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती की भंडीगुंड चूना पत्थर खान केम्मनगुडी लौह अयस्क खान और बिलीकलबेट्ट क्वार्टजाइट खान के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० सी० कोन्नूर होंगे, जिसका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, जो बन्दी गुण्डा चूना पत्थर खान, केम्मनगुंडी लौह अयस्क खान और बिलीकलबेट्ट क्वार्टजाइट खानों के पट्टा धारक हैं, के प्रबन्धतन्त्र का निम्नलिखित सत्रह कर्मचारियों (कुशल-श्रमिकों) को उनकी पिछले 7 से 8 वर्षों की लगातार सेवा के बावजूद स्थायी न करना और वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत न करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो ये कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं ?

1. श्री यू० करुणाकरन	आपरेटर ड्रिलिंग
2. श्री पी०टी० कोचुन्नी	,,
3. ,, सी०ए० गणेशन	,,
4. ,, गोनविन्दा सिंह राऊत	,,
5. ,, पी०एन० बासावाराज	कुशल-श्रमिक
6. ,, सुब्बेयाह	,,
7. ,, वेंकाटेश	,,
8. ,, करियप्पा	,,
9. ,, सुब्बाराज उर्स	,,
10. ,, सिरोमनी	,,
11. ,, अरमुगम	,,
12. ,, बी०के० सुब्बेयाह	,,
13. ,, टी०एम० थामस	,,
14. ,, पी०राजन नायर	,,
15. ,, टी०जी० भासकरन अचर	,,
16. ,, पी०जी० जार्ज	,,
17. ,, मुनिरथनम नायडू	,,

[सं० एल०-29011(15)/74-एल०आर० 4]

लाल फ़ ...

New Delhi, the 30th January, 1975

S.O. 363.—Whereas the Central Govenrnment is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to management of Bhandigund Lime Stone Mines, Kemmangundi Iron Ore Mines and Bilikalbetta Quartzite Mines of Messrs. Mysore Iron and Steel Limited, Bhadravati and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri M. C. Konnur as presiding Officer with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Messrs. Mysore Iron and Steel Limited who are the lease holders of Bandigunda Lime Stone Mines, Kemmangundi Iron Ore Mines and Bilikalbetta Quartzite Mines is justified in not confirming and in not granting annual increments to the following seventeen employees (Skilled Workers) inspite of their continuous service for the last 7 to 8 years? If not, to what relief are these employees entitled?

1. Sri U. Karunakaran	Operators Drilling
2. Shri P. T. Kochunni	"
3. Sri C. A. Ganeshan	"
4. Sri Govinda Singh Ravoot	"
5. Sri P. N. Basavaraj	Skiller Workers
6. Sri Subbaiah	"
7. Sri Venkatesh	"
8. Sri Kariappa	"
9. Sri Subbaraj Urs	"
10. Sri Siromani	"
11. Sri Armugam	"
12. Sri B. K. Subbaiah	"
13. Sri T. M. Thomas	"
14. Sri P. Rajan Nair	"
15. Sri T. G. Bhaskaran Achar	"
16. Sri P. G. George	"
17. Sri Munirathnam Naidu	"

[No. L-29011(15)/74-LR IV]

LALFAK ZUALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1975

का०आ० 364.—यत: केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के खण्ड (ख) के अनुसरण में श्री नि० प्र० दुबे, सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को श्री पी० एम० नायक के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है;

अत:, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1771 तारीख पहली जुलाई, 1974 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"श्री नि० प्र० दुबे,
सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय"।

[संख्या यू० 16012/16/74-एच० आई]

New Delhi, the 25th January, 1975

S.O. 364.—Whereas the Central Government has in pursuance of clause (b) of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri N. P. Dube, Secretary to the Government of India in the Ministry of Labour as a member of the Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri P. M. Nayak.

Now, therefore, in pursuance of section 8 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1771 dated the 1st July, 1974 namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government under clause (b) of section 8)", for the entry against item 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri N. P. Dube, Secretary to the Government of India, Ministry of Labour".

[No. U. 16012/16/74-HI]

का० आ० 365—यतः पंजाब की राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (थ) के अनुसरण में श्रीमति जी०के० सेखो, सचिव, पंजाब सरकार स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग को श्री जोगेन्दर सिंह के स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ।

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2763 तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (थ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे पद 19 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्रीमति जी० के० सेखो,
सचिव, पंजाब सरकार
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग,
चन्डीगढ़" ।

[सं० यू० 16012/1/74-एच० आई०]

आर० पी० नरूला अवर सचिव

S.O. 365.—Whereas the State Government of Punjab has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Smt. G. K. Sekhon, Secretary to the Government of Punjab, Health and Family Planning Department, to represent the State of Punjab on the Employees' State Insurance Corporation established under sub-section (1) of section 3 of the said Act, in place of Shri Joginder Singh.

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation No. S.O 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 19, the following entry shall be substituted namely :—

"Smt. G. K. Sekhon, Secretary to the Government of Punjab, Health and Family Planning Department, Chandigarh".

[No. U-16012/1/74-HI]

R. P. NARULA, Under Secy.

New Delhi, the 27th January, 1975

S.O. 366.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hirapur Manganese Mines, owned by Messers N.F. Mor Mines Proprietors, Tumsar, District Balaghat and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th January, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Dated 2nd January, 1975

Case No. CGIT/LC(R)(22) of 1974

(Notification No. L-27012/1/74-LR-IV, dated 23-9-1974)

PARTIES :

Employers in relation to the amanagement of Messrs. N.F. Mor Mines Proprietors, Tumsar District Bhandara (Maharashtra State) in relation to their Hirapur Manganese Mines at Balaghat (Madhya Pradesh) and their workman.

APPEARANCES :

For the Management.—None.

For the Workman.—Mr. K. Nutneshwar.

Industry : Maganese Mines **District :** Balaghat (M.P.)

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947. The question referred for the adjudication of this Tribunal as set out in the schedule to the reference is :—

"Whether the management of Messrs. N. F. Mor Mines Proprietors, Tumser District Bhandara (Maharashtra State) in relation to their Hirapur Manganese Mines at Balaghat (Madhya Pradesh) are justified in stopping Shri Shabeer Mohammad, Chowkidar of their Hirapur Manganese Mines from work with effect from the 11th September, 1973 without complying the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), Standing Orders and Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and the rules made thereunder ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

The dispue on behalf of the workman who was employed in Hirapur Manganese Mines at Balaghat was raised by the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Balaghat, hereinafter called the Union. It was stated that the management of the Mines had wrongfully terminated the services of the workman, Shabeer Mohammad, Mines Chowkidar.

It appears that the conciliation proceedings took place before the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara and also before the Assistant Labour Commissioner (Central) Bhopal. The latter closed the case as the representative of the workman failed to attend the conciliation proceedings on 27-12-1973. Thereafter, the Union's representative wrote to the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara informing him that he was not able to attend the discussion

on 27-12-1973 because he could not get intimation in time and requested him to re-open all such cases otherwise he would go on hunger strike before his office. Eventually, all this case and certain other cases were re-opened by the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara and parties were asked to attend the joint discussions/conciliation proceedings on 25-3-1974. The management by a telegram informed the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara that as the case had already been closed, the management will not attend the discussions on 25-3-1974 as fixed. The management was again asked to attend the discussions on 25-3-1974. The management/by a telegram requested the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara to adjourn the proceedings. Accordingly the discussions fixed for 25-3-1974 were adjourned to 19-4-1974 and the parties were requested to attend the proceedings. The Union's representative came to the office of the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara on 19-4-1974 but no one appeared on behalf of the management nor any information was received from it regarding its inability to attend the proceedings on that date. The Union's representative contended before the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara that since the termination of Shabeer Mohammad's services by the management was without any notice and also without complying with the the provisions of the Payment of Wages Act, Standing Orders and Industrial Disputes Act, it was illegal and, therefore, the workman should be reinstated with full back wages. Thereafter, exparte proceedings were conducted and the conciliation proceedings before the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara ended in failure.

Notices were issued by this Tribunal to the parties for filing their written statements but neither the management nor the Union have filed any written statement. A telegram dated 1-1-1975, has been received by this Tribunal. It says :—

> "Reference Case CGIT/LC (R) (22/74 fixed for second January Hirapur Mining Lease expired on 20-3-72. Final payment made to Sabir Mohammad on 15-9-1974 and settlement done with workman. Kindly close the proceedings Narsinghda Fatechand."

No one has appeared on behalf of the parties before this Tribunal today. In view of the aforesaid telegram that final payment has been made to Shabeer Mohammad, he is not entitled to any further relief. I make my award accordingly. Parties will bear their own costs.

[No. L. 27012/1/74-LR. IV]

S. N. KATJU, Presiding Officer

S.O. 367.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the industrial dispute between the employers in relation to the Beas Dam Project, Talwara and their workmen, which was received by the Central Government on the 17 January, 1975.

BEFORE SHRI JOGINDER SINGH, DEPUTY LABOUR COMMISSIONER, PUNJAB (NOW JOINT LABOUR COMMISSIONER, PUNJAB) SOLE ARBITRATOR.

IN THE MATTER OF ARBITRATION BETWEEN WORKMEN AND THE MANAGEMENT OF BEAS DAM PROJECT, TALWARA.

PRESENT

1. Shri Joginder Singh,
   Joint Labour Commissioner, Punjab, (Sole Arbitrator)

APPEARANCE

1. Shri K. K. Jaggia, Superintending Engineer,
2. Shri Kuldip Singh, Personnel Officer, } For the management
3. Shri. Padamjit Singh Assistant Personnel Officer (Legal)

4. Shri Daulat Singh Chauhan, General Secretary, Workers Union Beas Dam Project, Talwara. — For the workman

AWARD

The industrial dispute between the employer in relation to Beas Dam Project, Talwara and its workman represented by the Workers Union, Beas Dam Project, Talwara regarding reversion of Shri Milkhi Ram, Junior Driller, was referred to me for arbitration vide Government of India Notification dated 16-4-1974. The terms of reference were as under :—

> "Whether the action of the Management of Beas Dam Project, Talwara in reverting Shri Milkhi Ram, Junior Driller as Beldar with effect from 29-11-1972 is legal and Justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

As per the said notification, I was required to pronounce the award within 6 months from the date of reference and which could be extended on the mutual consent of the parties to the dispute. Because of non-availability of the parties for arbitration proposes the award could not be finalised within 6 months and the parties gave it in writing for extension of the time limit for a further period of 3 months which was accepted by me.

During the arbitration proceedings the management was represented tby Shri K. K. Jaagia, Superintending Engineer (Admn.) alongwith Shri Kuldip Singh, Personnel Officer and Shri Padamjit Singh, Assistant Personnel Officer (Legal), whereas the case of the workman was represented by Shri Daulat Singh Chauhan, General Secretary of the Workers Union, Beas Dam Project, Talwara.

There were four hearings in this case At Hoshiarpur on 14-8-1974 at Chandigarh on 10-10-1974 and 6-1-75 and also at Talwara on 2/3-1-1975. In support of their case the management produced one witness Shri Sat Pal, S. D. O. who was an enquiry officer against Milkhi Ram and another documents namely :—

1. Copy of chargesheet,
2. Copy of enquiry report,
3. Copy of show cause notice,
4. Copy of punishment order,
5. Original statement of the following persons :—
   (i) Gurcharan Singh, Foreman (Special),
   (ii) Maan Chand, Beldar,
   (iii) Ajit Singh, Sectional Officer,
   (iv) Ghammi Ram, Driller,
   (v) Bhagat Singh, Executice Engineer, &
   (vi) Suram Chand, Junior Driller.

The Union produced the following witness in support of their defence :—

(i) Kundan Singh, Driller,

(ii) Ghammi Ram, Driller,

(iii) Harbans Singh, Driller.

The representative of the workman filed the statement of claims vide his Memo dated 10-6-1974, a copy of the same was enclosed to the employer and the representative of the employer filed rejoinder of the same on 24-7-1974.

When the arbitration proceedings started on 14-8-1974 the representative of the management Shri K. K. Jaagia, raised certain preliminary legal objections. On the basis of the pleadings of the parties the following issues were framed :— Preliminary Issues

(1) Whether the instant reference constitutes an industrial dispute within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 ?

(2) Whether the arbitration agreement referring the industrial dispute for arbitration is valid ?

On Merits

Whether the action of the management in reverting Shri Milkhi Ram, Junior Driller to Beldar is justified ? If not to what relief he is entitled ?

While contesting the first preliminary issue the representative of the employer Shri K. K. Jaagia, Superintending Engineer pleaded that the instant dispute is an individual dispute regarding reversion of a workman. Since it has been taken up by Shri Daulat Singh Chauhan, General Secretary of the Workers Union, Beas Dam Project, Talwara in his personal capacity without any authority from the workers Union or support from other co-workers through a resolution or by other means, as such it does not constitute an industrial dispute under section 2 (K) of the Industrial Disputes Act, 1947. He further argued that Shri Daulat Singh Chauhan, General Secretary of the Workers Union, Beas Dam Project, Talwara, in spite of the categorical objection of the management has failed to produce any resolution of collective body of the workers or of the union authorising him to take up the dispute with the employer. In the absence of which the individual dispute regarding reversion of a workman cannot be taken up as an industrial dispute under section 2 (K) of the Act. He also contended that since there was no industrial dispute within the meaning of section 2 (K) of the Act, the Arbitrator has no jurisdiction to proceed with the arbitration. He relied upon the judgments reported in 1962-II-LJJ-93 (Visalakhi Mills Ltd., Mudrai and others) decided by Madras High Court and also 1965-I LLJ-95 (Nellai Cotton Mills, Tirunelveli V/S Labour Court, Mudrai and others). Shri Jaagia while replying on a judgment by the Division Bench of Madhya Pradesh High Court in the case of Singh (K. P.) and other V/S Gokhale (S. K.) and others reported in 1970-I-LLJ-125 and other decision by the Division Bench of Madras High Court in the case of Vallamalai Estate, Valparai V/S workers of Valamala Estate, Valparai and other reported in 1973-I-LLJ-273 argued that even the action of the employer in entering into an arbitration agreement cannot operate as estoppel for the employer from pleading that what has been referred for arbitration does not constitute an industrial dispute. From the perusal of these judgements the law is fairly settled, that the jurisdiction of the arbitrator and adjudicator is entirely dependent on the existence or apprehension of an industrial dispute and might note stop the parties to plead in even the joint reference that what was referred does not constitute an industrial dispute. I have carefully gone through both the judgments cited in the 1965-I-LLJ-95 and 1962-II-LLJ-93. Their purusal reveal that it is necessary to enquire whether the union which has espoused the cause of a workman, fairly claimed a representative character. The instant case can be distinguished from the two cases to the extent that in both these cases the disputes were taken up by outside unions when the unions exclusively of the workmen of these factories were functioning, whereas this dispute has been taken up by workers of the Project itself. But one thing is clear that in the face of objection raised by the management the onus to prove by leading evidence that what has been referred for arbitration constitute an industrial dispute as defined under the Industrial Disputes Act, 1947 is on the union raising the dispute.

In this case, although it is indicated in the printed form of the union that the union is recognised, but the representative of the workman has failed to bring and evidence on the record to this effect. Had he led any such evidence, the position would have slightly changed. The union was required to bring on record, evidence to the effect that :—

(i) Workers Union, Beas Dam Project, Talwara is a recognised union,

(ii) Shri Milkhi Ram was a member of the union before or at the time of reference of his case for arbitration,

(iii) The workers of the Project had collective interest in the industrial dispute which they should have shown in the form of a resolution of general body meeting or in any other manner.

Since the representative of the union has failed to discharge his onus by bringing on record and hereby proving that what was referred for arbitration was in fact an industrial dispute within the meaning of section 2 (K) of the Industrial Disputes Act, 1947, I decide the preliminary issue No. 1 in favour of the management and against the union.

Preliminary Issue No. 2

As regards the second preliminary issue, the representative of the employer, Shri K. K. Jaagia, pleaded that the agreement referring the industrial dispute for arbitration is not valid on the following grounds :—

(i) Under Rule 8 of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 the arbitration agreement is required to be authenticated by the employer himself, whereas in the instant case it has been authenticated by Sh. Padamjit Singh, Assistant Personnel Officer (Legal) who can with no stretch of imagination be considered as an employer. The representative of the workman pointed out that since the parties had voluntarily agreed for reference of the dispute for arbitration, the employer is now estoppel from taking up this plea.

(ii) Shri Padamjit Singh, Assistant Personnel Officer (Legal) who was duly authorised by the employer to settle the dispute through conciliation, filed an authority letters given to him by the employer before the Assistant Labour Commissioner (Central) during the conciliation proceedings. Under section 36 of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rules 36, the parties appearing in the proceedings under this Act through their agents (authorised representative) are bound down by the action of such agents. Shri Padamjit Singh was duly authorised to settle the dispute in conciliation or otherwise by appearing before the Assistant Labour Commissioner (Central). It cannot be assumed that this authority was just for appearance and not comitting anything before the Assistant Labour Commissioner (Central) by way of a settlement of the dispute. I am, therefore, of the view that he was competent to settle the dispute before the Conciliator in case on the spot settlement was possible or through some reference for arbitration or adjudication. Hence I over rule this objection of the employer as the agent appearing with the authority of the employer is a competent person to authenticate the reference for arbitration. Preliminary issue No. 2 is decided against the management.

The law presupposes the existence or apprehension of an industrial dispute, before the Tribunal or Arbitrator could proceed to adjudicate the same. Since I have decided the preliminary issue No. 1 that, what was referred was not a valid one, I as an Arbitrator have no jurisdiction to proceed and to decide the same on merits (1967-I-LLJ-577-judgment by the Division Bench of the Punjab High Court in the case of Karnal Distillery Company Ltd; V/S their workmen), I, therefore, reject the reference on this very ground, that what has been referred for arbitration, does not constitute an industrial dispute under the Industrial Disputes Act, 1947, without entering into the merits of the case.

JOGINDER SINGH, Joint Labour Commissioner.

Dated, Chandigarh, the 13th Jan, 1975

[No. L. 42012 (18)/74-LR. III]
JOGINDER SINGH, Joint Labour Commissioner.
(Special),

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1975

का० आ० 368.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वाराणसी बाटलिंग कम्पनी, 42-43 गौतम बुद्ध राजपथ वाराणसी, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ।

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[संख्या एस०-35019(119)/74-पी० एफ०-2(i)]

New Delhi, the 28th January, 1975

S.O. 368.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Varanasi Bottling Company, 42-43 Gautam Budh Rajpath, Varanasi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1973.

[No. S. 35019(149)/74-PF. II(i)]

का० आ० 369.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर० के० इंजीनियरिंग इन्टर प्राइजेज, बी०-86 इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, राजाजी नगर, बंगलौर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अत., अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतदद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०-35019(226)/74-पी०एफ०-2]

S.O. 369.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs R. K. Engineering Enterprises, B. 86 Industrial Estate, Rajajinagar Bangalore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1974.

[No. S. 35019(226)/74-PF. II]

का० आ० 370—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री उदयलक्ष्मी राइस एण्ड फ्लोर मिल, मंछलीपटनम, आंध्रप्रदेश, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अत., अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी

[सं० एस०-35019(30)/74-पी०एफ०-2]

S.O. 370.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sri Udayalokshmi Rice and Flour Mill, Machilipatnam, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1974.

[No. S. 35019(30)/74-PF. II]

का० आ० 371—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि पांडिचेरी को-आपरेटिव प्रिंटिन्ग एण्ड पब्लिशिंग सोसाइटी लिमिटेड, 16 मेरीन स्ट्रीट, पांडिचेरी, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मकारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियमम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ।

अत., अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (34) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०-35019(53)/74-पी० एफ० 2]

S.O. 371.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Pondichery Co operative Printing and Publishing Society Limited, 16, Marine Street Pondichery, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1974.

[No. S. 35019(53)/74-PF. II]

का० आ० 372.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्ट्रोम क्राफ्ट कन्ट्रोल्स, ब्लाक बी० 118-124 घाटकोपर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर, मुम्बई, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के मई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[संख्या एस०-35018(61)/74-पी०एफ०-2)(i)]

S.O. 372.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Strom-Kraft Controls, Block D-118-124, Ghatkopar, Industrial Estate, Lal Bahadur Shastri Marg, Ghatkopar, Bombay have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of May, 1973.

[No. S. 35018(61)/74-PF. II(i)]

का० आ० 373.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् मैसर्स स्ट्रोम-क्राफ्ट कंट्रोल्स, ब्लाक डी०-118-124 घाटकोपर, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर, मुम्बई, नामक स्थापन को 31 मई, 1973 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०-35018(61)/74-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 373.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiries into the matter, hereby specifies with effect from the 31st day of May, 1973, the establishment known as Messrs. Strom-Kraft Controls, Block D-118-124, Ghatkopar, Industrial Estate, Lal Bahadur Shastri Marg, Ghatkopar, Bombay, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(61)/74-PF. II(ii)]

का० आ० 374—यत, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टायर्स इंडिया सेल्स कारपोरेशन, राधाकृष्ण सदन, बिच्चोलिम, गोआ, जिसके अंतर्गत (1) पंजी (2) वास्की-डे-गामा (3) सनबोर्डेम-कर्चोरिम स्थित इसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के नवम्बर, के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[संख्या एस०-35018(65)/74-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 374.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Tyres India Sales Corporation, Radhakrishna Sadan, Bicholim, Goa, including its branches at (1) Panaji (2) Vasco-de-gama (3) Sanvordem-Curchorem, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1973

[No. S 35018(65)/74-PF. II(i)]

का०आ० 375.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन कुटुम्ब निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जाँच करने के पश्चात मैसर्स टायर्स इण्डिया सेल्स कारपोरेशन, राधाकृष्ण सदन, बिच्चोलिम, गोआ जिसके अन्तर्गत (1) पंजी (2) वास्को-डे-गामा (3) सनबोर्डेम-कर्चोरिम स्थित इसकी शाखाएं भी है, नामक स्थापन को 30 नवम्बर, 1973 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[संख्या एस०-35018(65)/74-पी०एफ०-II(ii)]

S.O. 375.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th day of November, 1973, the establishment known as Messrs. Tyres India Sales Corporation, Radhakrishna Sadan, Bicholim, Goa including its branches at (1) Panaji (2) Vasco-de-gama (3) Sanvordem-Curchorem, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(65)/74-PF. II(ii)]

का० आ० 376 – यत, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आनेस्ट एलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्लाट सं० ए० 39, वाग्ले एस्टेट, रोड नं० 11 थाना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०-35018(84)/74-पी०एफ०-2]

S.O. 376.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Honest Electrical Works, Plot No. A 39, Wagle Estate, Road No. 11, Thana, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtyfirst day of March, 1973.

[S. 35018(84)/74-PF. II]

का० आ० 377—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिन्दिया कैमिकल्स लिमिटेड, 11 स्प्रौट रोड, वेक फील्ड हाउस, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई, जिसके अन्तर्गत (1) 19 राजेन्द्रनाथ मुखर्जी रोड, कलकत्ता, (2) 3/8 आसफअली रोड नई दिल्ली, तथा (3) काइथनेस हाल 310/11 लिंघी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास स्थित उसकी शाखाएं भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 की जुलाई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[संख्या एस०-35018(82)/74-पी०एफ०-2]

S.O. 377.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Mindia Chemicals Limited, 11 Sprott Road, Wakefield House, Ballard Estate, Bombay, including its branches at (1) 19, Rajendra Nath Mukherjee Road, Calcutta (2) 3/8 Asaf Ali Road, New Delhi and (3) Caithness hall, 310/11, Linghi Chetty Street, Madras have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1973.

[No. S. 35018(82)/74-PF II]

का० आ० 378—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मसाला वाला को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मसालावाला बैंक बिल्डिंग, 74, टान्डेल, स्ट्रीट, एस०बी०पी० रोड,, मुम्बई, जिसके अन्तर्गत इसकी इमामवाडा स्थित शाखा, करीमाबाद-116 इमामवाडा रोड, मुम्बई भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ।

अत, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा, (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०-35018(99)/74-पी०एफ०-2]

S.O. 378.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Masalawala Co-operative Bank Limited, Masalawala Bank Building, 74 Tandel Street, S. V. P. Road, Bombay, including its branch at Imamwada, Karimabad 116, Imamwada Road, Bombay, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1970.

[No. S. 35018(99)/74-PF. II]

का० आ० 379—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाम्बे सर्वोदया प्रैस, विवेक इण्डस्ट्रियल एस्टेट यूनिट सं० 9—मोगल लेन (उत्तरी) माहिम, मुम्बई-6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अत, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 की मई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०-35018(75)/74-पी०एफ०-2]

S.O. 379.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bombay Sarwodaya Press, Vivek Industrial Estate, Unit No. 9, Mogul Pane (North) Mahim, Bombay-6 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952, (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the Thirty first day of May, 1973.

[No. S. 35018(75)/74-PF. II]

का० आ० 380—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नारायण टाकीज, कलूमल गार्डन, चमन गंज, कानपुर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(220)/74-पी० एफ० 2]

S.O. 380.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Narain Talkies, Kalloomal Garden, Chamanganj, Kanpur have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1972.

[No. S. 35019(220)/74PF-II]

का० आ० 381.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेशम सिंह एण्ड कम्पनी, 5, पी० डी० मेलो रोड, मुम्बई-9, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(85)/74-पी०एफ० 2]

S.O. 381.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in the relation to the establishment known as Messrs. Reshamsingh and Company 5, P. D. Mello Road, Bombay-9; have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1973.

[No. S. 35018(85)/74-PF. II.]

का० आ० 382—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि केरल स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवेलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पेरूरकादा, त्रिवेन्द्रम नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन लागू करती है।

यह अधिसूचना, 1973 के अक्तूबर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(180)/73-पी०एफ० 2]

S.O. 382.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Kerala State Electronics Development Corporation Limited, Peroorkada, Trivendrum, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1973.

[No. S. 35019(180)/73-PF-II]

का० आ० 383.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अशोक आर्ट प्रिन्टरी, खमासा गेट के निकट, नगर के सामने, अहमदाबाद नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(216)/74-पी० एफ० 2]

S.O. 383.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ashok Art Printery, Near Khamasa Gate, Opposite Municipal Corporation, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1973.

[No. S. 35019(216)/74-PF. II]

का० आ० 384.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोतो पैक, गतगुरु एस्टेट, विश्वेश्वर नगर, गोरे गाव (पूर्व) मुम्बई-63 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस०-35018(66)/74-पी०एफ० 2 (i)]

S.O. 384.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Roto Pack, Satguru Estate, Vishweshwar Nagar, Goregaon (East) Bombay-63, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1974.

[No. S. 35018(66)/74-PF. II(i)]

का०आ० 385.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् मैसर्स रोटो पैक, सतगुरु एस्टेट, विश्वेश्वर नगर, गोरे गांव (पूर्व) मुम्बई-63 नामक स्थापन को 31 मार्च, 1974 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस०-35018(66)/74-पी०एफ०-2(ii)]

बी० आर० जैन, अवर सचिव

S.O. 385.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st day of March, 1974, the establishment known as Messrs Roto Pack, Satguru Estate, Vishweshwar Nagar, Goregaon (East) Bombay-63, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(66)/74-PF. II(ii)]

B. R. JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1975

का०आ० 386.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, वर्ष 1973-74 के खाते का विवरण सहित वर्ष 1974-75 के दौरान कोयला खान श्रमिक गृह और साधारण कल्याण निधि के साधारण कल्याण खाते में हुई प्राप्ति और उससे हुए व्यय का निम्नलिखित प्राक्कलन, तथा वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त निधि के साधारण कल्याण खाते से वित्त पोषित कार्यकलापों की रिपोर्ट प्रकाशित करती है, अर्थात् :—

भाग I

1974-75 के दौरान प्राप्ति और व्यय का प्राक्कलन साधारण कल्याण खाता

प्राप्ति	व्यय
3,60,48,000 रु०	3,43,49,000*

*इस में 5,80,000 रु० की उधार की राशि सम्मिलित है, (1,80,000 रु० कोयला खदानों के स्वामियों को औषधालय सेवाओं का स्तरमान ऊंचा करने के लिये, 1,00,000 रु० का उधार झरिया जलबोर्ड को, तथा 3,00,000 रु० का उधार सहकारी उधार सोसाइटी के लिये।)

इसमें 16,54,000 रु० की वह राशि जो 'अनिश्चित' है भी सम्मिलित है, और उसे वसूलियों के ब्यौरों में दिखाया गया है।

भाग II

वर्ष 1973-74 का लेखा-विवरण साधारण कल्याण खाता

	प्राप्ति	व्यय
1 1-4-1973 को प्रारम्भिक अतिशेष .	(—) 69,63,000	
2. वर्ष के दौरान व्यय .		3,07,26,000 (क)
3 वर्ष के दौरान प्राप्ति .	3,79,54,000	
4 31-3-74 को अन्तिम अतिशेष .		2,65,000
	3,09,91,000	3,09,91,000

(क) इसमे 1,00,000 रु० सम्मिलित है, जो कि कोयला खदानों के स्वामियों को औषधालय सेवाओं का स्तरमान ऊंचा करने के लिये दिया गया 'उधार' है और 15,23,000 रु० "अनिश्चित व्यय" की राशि भी सम्मिलित है जो कि स्टाक और भण्डार से सम्बन्धित सव्यवहारों को अन्तिम रूप दिये जाने तक के लिये है।

टिप्पण—ऊपर दिखाए गए आकड़े अनन्तिम है, क्योंकि 1973-74 का लेखा अभी महालेखापाल, बिहार द्वारा बन्द नहीं किया गया है।

भाग III

वर्ष 1973-74 के दौरान वित्तपोषित क्रियाकलापों की रिपोर्ट

1 चिकित्सकीय सुविधाएं

(क) अस्पताल : तीन केन्द्रीय, धनबाद, आसनसोल और मानेन्द्रगढ़ में एक-एक और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में स्थित 12 क्षेत्रीय अस्पताल कार्य करते रहे। धनबाद, आसनसोल और मानेन्द्रगढ़ के केन्द्रीय अस्पतालों की शैय्या संख्या क्रमश: 300, 350 और 100 थी। चान्दा कोयला क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अस्पताल की स्थापना के बारे में सक्रिय रूप से विचार हो रहा था। अस्पताल को बल्लारपुर में स्थापित करने के लिये अन्तिम रूप मे विनिश्चय कर लिया गया है। तालचर कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अस्पताल में, निधि द्वारा उस कोयला क्षेत्र मे एक क्षेत्रीय अस्पताल की व्यवस्था के विकल्प के रूप मे यथोचित आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान देते हुए एक विशेष वार्ड की व्यवस्था के बारे में सक्रिय रूप से विचार हो रहा था।

(ख) औषधालय : मुग्मा कोयला क्षेत्र में एक एलोपैथिक स्थायी औषधालय, असम कोयला क्षेत्र में एक चल चिकित्सकीय एकक और विभिन्न कोयला क्षेत्रों मे 29 आयुर्वेदिक औषधालय कार्य करते रहे। अपेक्षित आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए झरिया कोयला क्षेत्र मे पथेरडिह में स्थापित आयुर्वेदिक औषध-शाखा भी कार्य करती रही।

(ग) कुटुम्ब कल्याण और प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र : इस संस्था के प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पताल से सलग्न कुटुम्ब कल्याण केन्द्र कार्यरत रहे। इसके अतिरिक्त इस संस्था द्वारा विभिन्न कोयला क्षेत्रों में पहले से स्थापित ऐसे केन्द्र प्रशिक्षित महिला-स्वास्थ्य-परिदर्शक के भारसाधन में स्वतन्त्र एककों के रूप में कार्य करते रहे। चांदा कोयला क्षेत्र के कोयला खान कर्मकारों के फायदे के लिए सरकारी अस्पताल चांदा से सलग्न ब्लाक

बराबर काम करता रहा । आसनसोल, झरिया और हजारीबाग खान स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा 37 प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे थे, किन्तु कतिपय विहित प्रतिमानों के पालन न किये जाने के कारण निधि ने सम्प्रति उनके अनुरक्षण के लिए सहायतार्थ अनुदान बन्द कर दिया है ।

(घ) औषधालय सेवाओं को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता .—कोयला खदान कर्मकारों और उनके आश्रितों के फायदे के लिए कोयला खदानों में कोयला खदान प्रबन्ध तंत्रों को औषधालय सेवाओं का स्तरमान सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से सहायतार्थ अनुदान देने की स्कीम चालू रखी गई तथा कोयला खान प्रबंधकों को इस वर्ष के दौरान कोयला खान के कर्मकारों के लिए औषधालय सेवाएं प्रदान करने के हेतु 8,28,591.24 रु० की रकम दी गई । कोयला खदान स्वामियों को अपने कर्मकारों के फायदे के लिए अधिक औषधालय सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता देने की स्कीम चलाई गई थी । इस अवधि के दौरान 1,00,000.00 रु० की राशि दी गई।

(ङ) क्षयरोधी उपाय : क्षय पीड़ित कोयलाखदान कर्मकारों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए इस संस्थान के अपने यक्ष्मा अस्पतालों में 312 शैय्याओं की व्यवस्था के अतिरिक्त उनके लिए विभिन्न यक्ष्मा आरोग्याश्रमों में 61 शैय्याएं आरक्षित रहीं । यक्ष्मा का गृहोपवर्ती इलाज चलता रहा और इस स्कीम के अधीन इलाज कराने वाले यक्ष्मा रोगी को कार्यक्रम के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाना भी चालू रहा । इस अवधि के दौरान इस स्कीम पर 5,94,830.19 रु० की राशि लगाई गई ।

(च) परिवार नियोजन सेवाएं : कोयला खान श्रम आवास और साधारण कल्याण निधि अस्पतालों में तथा उस प्रयोजन के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खोली गई क्लीनिकों में, परिवार नियोजन के बारे में मुफ्त वितरण बराबर चलता रहा । कोयला खान स्वामियों को परिवार नियोजन के लिए, सहायक अनुदान की स्कीम बराबर प्रवृत्त रही । 12 परिवार नियोजन केन्द्र, जिनमें से तीनों केन्द्रीय अस्पतालों में एक-एक और शेष 9 निधि के विभिन्न क्षेत्रीय अस्पतालों में कार्य करते रहे ।

(छ) पुनर्वास : धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में से प्रत्येक के साथ संलग्न पुनर्वास केन्द्र कार्य करते रहे । मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में छिन्दवाड़ा स्थित पुनर्वास केन्द्र का उद्घाटन कर दिया गया और उसने अप्रैल, 1973 से कार्य करना आरंभ कर दिया है । पश्चिमी बंगाल में सिद्धाबाड़ी स्थित पुनर्वास एवं रोगनिवृत्तालय आरंभ करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ज) अन्य चिकित्सीय कार्यकलाप : चिकित्सकीय और लोक स्वास्थ्य की दिशा में इस संस्था के अन्य क्रिया कलाप ये हैं—कैंसर, कोढ़ और मानसिक रोगों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में रक्त बैंक चलाना, कर्मकारों को ऐनकों और कृत्रिम दंतावली का मुफ्त प्रदाय, मलेरिया तथा फिलेरिया नियंत्रण कार्य आदि, आदि ।

2. शैक्षिक तथा आमोद-प्रमोद विषयक सुविधाएं

(क) इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को प्रकाश में लाने वाले कुछ सुसंगत आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(i)	बहुउद्देश्यीय संस्थान	63
(ii)	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	64
(iii)	महिला कल्याण केन्द्र	63
(iv)	दीपक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	156
(v)	कोयला कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति	546
(vi)	विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए छात्रावास	2
(vii)	अवकाश-गृह	2

(ख) खेल और क्रीड़ा .—कोयला खान के कर्मकारों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक वर्ष खेल और क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है । वर्ष 1973 के दौरान विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं के लिए संस्था द्वारा 1,47,755 रु० की रकम खर्च की गई थी ।

(ग) अन्य क्रिया-कलाप : इस सम्बन्ध में दी गई अन्य सुविधाओं में (1) शैक्षिक संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान, (2) कोयला खनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति (3) कोयला खनिकों के लिए क्रीड़ा और खेल कूद की व्यवस्था, (4) फिल्मों का प्रदर्शन (5) खानों में दुर्घटनाओं में मृत्यु प्राप्त कोयला खदन कर्मकारों की पत्नियों और विद्यालय जाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था आदि हैं ।

3. जल-प्रदाय स्कीमें

इस वर्ष के दौरान, 13,01,478.35 रु० की रकम जल-प्रदाय स्कीमों पर खर्च की गई है । यह संस्था, यथास्थिति, कोयला खदान प्रबंधतंत्रों और अन्य निकायों को जल-प्रदाय स्कीमों के लिए संवीक्षित व्यय के कुल खर्च पर 50 प्रतिशत तक सहायतार्थ अनुदान देती रही । पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित, निधि द्वारा अंशतः वित्तपोषित दो एकीकृत जल-प्रदाय स्कीमें, कार्याधीन हैं ।

कुओं की खुदाई—

अब तक पूरे किए गए कुओं की संख्या 259 है । रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान, विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 8 कुएं खोदने की स्वीकृति दी गई थी ।

4. सहकारी आंदोलन

इस वर्ष कोई भी नए प्राइमरी स्टोर, सहकारी प्रत्यय सोसाइटी और थोक केन्द्रीय सहकारी स्टोर नहीं खोले गए । पुनरीक्षणाधीन अवधि के अन्त में कोयला खदानों के कर्मकारों के सहकारी स्टोरों और प्रत्यय सोसाइटियों की संख्या 579 रही । इनमें 12 थोक या केन्द्रीय सहकारिता भण्डार भी थे जो संगठन द्वारा चलाए जा रहे थे ।

[सं० यू० 16013/3/74-एम० 2]

बी० के० सक्सेना, अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 1975

S.O. 386.—In pursuance of Sub-section (5) of section (5) of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), the Central Government hereby publishes the following estimates of receipts into and expenditure from the General Welfare Account of the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund during the year 1974-75 together with a statement of the account for the year 1973-74 and a report on the activities financed during the year 1973-74 from the General Welfare Account of the said Fund, namely :—

PART I

Estimates of Receipts and Expenditure during 1974-75

General Welfare Account

Receipt	Expenditure
Rs. 3,60,48,000	Rs. 3,43,49,000*

* Provision includes Rs. 5,80,000/–being 'Loan' (Rs 1,80,000 to the Colliery owners for raising the standard of dispensary services Rs. 1,00,000/–Loan to Jharia Water Board and Rs. 3,00,000/—loan for Co-operative Credit Societies.

This also includes Rs. 16,54,000/—under 'Suspence' which has been shown in the details of recoveris.

PART II

Statement of Account for the year 1973-74

GENERAL WELFARE ACCOUNT

Receipt		Expenditure
1 Opening balance as on 1 4 73	(--) 69,63,000	
2 Expenditure during the year		3,07, 6000 a)
3 Receipt during the year	3,70,54,000	
4 Closing balance as on 31 3.74		2,65,000
	3,09,91,000	3,09,91,000

(a) Includes Rs. 1,00,000 being 'Loan' to Colliery owners for raising the standard of dispensary services and Rs. 15,23,000 "Suspense Purchase" to accommodate transactions relating to stock and stores pending finalisation.

N B—The figures shown above are provisional as the account for 1973-74 has not yet been closed by the Accountant General, Bihar.

PART III

Report on Activities financed during the year 1973-74

1. Medical Facilities. (a) Hospitals—The 3 Central Hospitals, one each at Dhanbad, Asansol and Manendragarh and 12 Regional Hospitals situated in different coalfields continued to function The bed strength of the Central Hospitals at Dhanbad, Asansol and Manendragarh was 300, 350 and 100 respectively. The proposal for the establishment of a Regional Hospital in Chanda Coalfield remained under active consideration. The Hospital has finally been decided to be set up at Ballarpur. Provision of a specialised ward in the National Coal Development Corporation's Hospital in Talcher Coalfield by giving suitable recurring and non-recurring grant as an alternative to Fund's providing a Regional Hospital in that Coalfield remained under active consideration.

(b) Dispensaries.—One Allopathic Static dispensary in Mugma Coalfield, one Mobile Medical Unit in Assam Coal fields and 29 Ayurvedic Dispensaries in various coalfields continued to function. The Ayurvedic Pharmacy set up at Patherdih in Jharia Coalfield to manufacture required Ayurvedic Medicines also continued to function.

(c) Family Welfare and Maternity and Child Welfare Centres.—A Family Welfare Centre attached to each of the Regional Hospitals of the Organisation remained in operation. Besides, 8 such Centres already established by the Organisation in various Coalfield areas also continued to function as independent units under the charge of qualified Lady Health Visitors. For the benefit of the colliery workers in the Chanda Coalfield, the Block attached to the Government Hospital, Chanda, continued to function. 37 Maternity and Child Welfare Centres were being run by the Asansol, Jharia and Hazaribagh Mines Boards of Health but due to non-fulfilment of certain prescribed norms the Fund stopped paying grant-in-aid towards their maintenance for the present.

(d) Financial Assistance for improving Dispensary services—With a view to encourage the colliery management for improving the standard of dispensaries at the collieries for the benefit of colliery workers and their dependents, the scheme for the payment of grant-in-aid was continued and a sum of Rs. 8,28,591.24 was paid to the colliery managements during the year for providing medical facilities to the colliery workers In order to encourage the colliery owners to provide more dispensary services for the benefit of their workers, the scheme of payment of financial assistance was also continued. A sum of Rs. 1,00,000.00 was paid as loan during the period

(e) Anti T. B Measures—For the treatment of colliery workers and their dependents suffering from T. B., besides provision of 312 beds at the Organisation's own T.B. Hospitals, 61 beds remained reserved for them in different T.B. Sanatoria The scheme of Domiciliary T. B. treatment continued to function and payent of subsistence allowance to the T B. patients undergoing treatment under the Scheme also continued to be made according to schedule. A sum of Rs. 5,94,830.19 was incurred on this scheme during the period.

(f) Family Planning Services.—Free advice on Family Planning continued to be given and contraceptives supplied free of cost at the Coal Mines Labour Welfare Fund's Hospitals and at the Clinics opened for the purpose in various coalfields. The scheme for the payment of grant-in-aid to the Colliery owners for the Family Planning work continued to be in force. 12 Family Planning Centres—one each at three Central Hospitals and the remaining 9 at the different Regional Hospitals of the Fund were in operation.

(g) Rehabilitation—The Rehabilitation Centres attached to each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol continued to funcion The Rehabilitation Centre at Chhindwara in Madhya Pradesh coalfield was inauguarated and started functioning from April, 1973. The question of commissioning the Rehabilitation-cum-Convelescent Home at Sidhabari in West Bengal coalfield remained under active consideration.

(h) Other Medical Activities—Other important activities of the Organisation on the medical and public health sides were :—

Provision of facilities for the treatment of Cancer, Leprosy and Mental cases, running of Blood Bank at the Central Hospital at Dhanbad and Asansol, free supply of spectacles and dentures to the colliery workers, Malaria and Filaria Control operation etc etc.

2 Educational and Recreational Facilities—(a) Some relevant statistics high-lighting the important activities on this account are given below :—

(i) Multipurpose Institutes	.	.	63
(ii) Adult Education Centres	.	.	64
(iii) Woman Welfare Centres.			63
(iv) Feeder Adult Education Centres	...	...	156
(v) Scholarship to the children of colliery workers.	...	...	536
(vi) Boarding Houses for school going children.	.	...	2
(vii)Holiday Homes	..	...	2

(b) Games and Sports.—Games and Sports are held every year to provide recreation to colliery workers. During the year 1973 for organising various gamesand sports, a sum of Rs. 1,47,755 was spent by the Organisation.

(c) Other Activities—Other important facilities provided in this connection comprise of (1) grant-in-aid to the Educational Institutions (2) scholarship towards of coal miners (3) provision for games and sports amongst coal miners (4) exhibition of films (5) provision for financial assistance to the wives and school going children of colliery workers who died of accident in mines etc etc.

3. Water Supply Schemes.—During the year, a sum of Rs. 13,01,478.35 has been spent on Water Supply Schemes. The Organisation continued to pay grant-in-aid as prescribed in the Water Supply Scheme upto 50 per cent on the total cost of scrutinised expenditure, to the colliery managements. Two integrated water supply schemes executed by the State

Governments, of West Bengal and Bihar partly financed by the Fund remained under execution.

Sinking of Wells.—Total number of wells so far completed is 259. During the period under report, sanction was accorded to sinking of 8 wells in different coalfields.

4. Co-operative Movement.—No new Primary Stores, Credit Co-operative Societies and Wholesale or Central Co-operative Stores were opened during the year. The total number of Co-operative Stores and Credit Societies of colliery workers at the end of the period under review stood at 579. These included 12 Wholesale or Central Co-operative Stores already opened and continued functioning for colliery workers.

[No. Z. 16016/3/74-M. II]

B. K. SAKSENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1975

का०आ० 387.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1034, दिनांक 3 अप्रैल, 1962 द्वारा गठित क्विलोन स्थित श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो हो गया है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० जे० चेरियन को पूर्वोक्त रूप से गठित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है ।

[सं० एस-11025/12/74-एल०आर० I]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव

New Delhi, the 31st January, 1975

S.O. 387.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court at Quilon constituted by the Notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1034 dated the 3rd April, 1962;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri P. J. Cherian as Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S-11025/12/74-LR. II]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

का० आ० 388.—केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, हजारीबाग मण्डल, हजारीबाग को बिहार राज्य के खनन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3988 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, 'अध्यक्ष' के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"आयुक्त, हजारीबाग मण्डल, हजारीबाग (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 12(1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्ति)।"

[सं० बी० 22012/1/74-एम० आई०]

टी० एस० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

S.O. 388.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 12 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints the Commissioner Hazaribagh Division, Hazaribagh as the Chairman of the Mining Board for the State of Bihar and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 3938, dated the 22nd December, 1962, namely :—

In the said notification, against "Chairman" for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Commissioner, Hazaribagh Division, Hazaribagh, Appointed by the Central Government under clause (a) of section 12(1)."

[No. V-22012/1/74/MI]

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975